प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है।

मुंशी प्रेमचंद

वर्ष-04, अंक - 16 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 20 जनवरी 2022 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सानिया मिर्जा ने किया सन्यास का ऐलान

नई दिल्ली। भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, 2022 उनका आखिरी सीजन होगा और इसके बाद वो संन्यास ले लेंगी। सानिया ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेने के लिए गई हैं वहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सानिया को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद उन्होंने कहा कि, वो इस सीजन के बाद संन्यास को लेकर प्लानिंग कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि, वह इस सीजन पूरा खेल पाएंगी या नहीं, कह नहीं सकती हूं।

सानिया ने कहा कि, मैंने टेनिस कोर्ट में वापस आने, फिट होने, वजन कम करने और माताओं के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की है, नई माएं जितना हो सके अपने सपनों का पालन करें।

सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला डबल्स का खिताब भी सानिया मिर्जा ने जीतने में कामयाबी पाई थी। इसके अलावा मिक्स्ड डबल्स में सानिया 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। यकीनन सानिया के संन्यास लेने से टेनिस के एक युग का अंत होगा।

आमजन को परेशान करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, शिकायतों के निराकरण में अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। समय पर लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लंबित आवेदनों का निराकरण अभियान चलाकर किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों एसडीएम शहडोल और सहायक आयुक्त खरगोन को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सहित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम हेल्पलाइन में उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों, अधिकारियों, विभागों को बधाई दी और निम्न प्रदर्शन वालों को सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि, बिजली, साफ-सफाई, छात्रवृत्ति, सीवेज आदि की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, योजनाओं का लाभ देना और व्यवस्थाओं को बनाकर रखना गुड गवर्नेंस हैं। जिन विभागों की समस्याएँ ज्यादा हैं, उनकी समीक्षा की जाये। जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायतों की सतत समीक्षा हो। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की पेंडिंग नहीं रहे। उन्होंने कहा कि, शिकायतों के निराकरण के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राशन का व्यवस्थित ढंग से वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, राशन संबंधी शिकायतें सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने राजगढ़ और अशोकनगर कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि राशन गरीबों का भोजन है, इसमें शिकायतें नहीं मिलना चाहिए।

अर्पणा यादव मामले में नरोत्तम मिश्रा ने तंज कस यूपी में जीत का किया दावा

भोपाल। भाजपा ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई। अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट सीट से दावेदार माना जा रहा है, ये सपा के लिए बड़ी चोट है। मामले पर मध्यप्रदेश में भी बयानबाजी शुरू हो गई और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए यूपी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है।

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, भाजपा उत्तरप्रदेश में फिर से दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का भाजपा में आना ये बताता है कि, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी तो छोड़िए अपना परिवार भी नही संभाल पा रही हैं वो प्रदेश क्या संभालेंगे।

कुत्तों की नसबंदी के कलेक्टर ने दिए आदेश

माही की गूंज, रतलाम।

शहर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहां लगातार स्ट्रीट डॉग्स के मामले बढ़ते जा रहे है, अपनी ही गलियों से गुजरना लोगों के लिए मुहाल हो गया है। जिस कारण रोज शहर में बड़े व छोटे बच्चें जिला अस्पताल पहुंच रहे है। शहर में न सिर्फ़दिन में बल्कि देर रात तक आवारा कुत्तों का झुण्ड सड़कों पर घूमता रहता है। इन झुंड में कुत्तों की संख्या भी 25 से 50 तक होती है।स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से छुटकारा पाने के लिए और इन डॉग बाइट के बढते मामलों को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने अब शहर में घूमते आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने का फैसला किया है। इसके लिए एजेंसी को यह काम सौंपा गया है।

इसके अलावा कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने अब शहर में कुत्ता पालने वालों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसके लाइसेंस का शुल्क एक हजार रुपए प्रतिवर्ष के लिए तय किया गया है। वहीं 1 व्यक्ति सिर्फ2 डॉग ही पाल सकता हैं। इसके कारण शहर में पालतू कुत्तों की संख्या की जानकारी भी रहेगी और सड़क के कुत्तों की नसबंदी का कार्य शुरू करवा दिया है। इस कार्य के लिए शहर के ट्रेंचिंग ग्राऊंड के पास एक छोटा हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। जहां कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, और 2 से 3 दिन इन कुत्तों को ऑब्जरवेशन में यहां रखने के लिए व्यवस्था भी की गई है।

पेट्रोल-डीजल पर नहीं लेकिन शराब का टैक्स घटा दिया - कमलनाथ

भोपाल। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के बजाए शराब पर टैक्स कम कर दिया गया है। इस प्रकार सरकार ने बता दिया है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। कमलनाथ ने कहा कि, शिवराज सरकार का शराब प्रेम एक बार फिर उजागर हो गया है। मध्यप्रदेश में अब शराब सस्ती हो जाएगी क्योंकि उस पर गवर्मेंट ड्यूटी कम कर दी गई है। जबकि पेट्रोल और डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। करो में कोई राहत नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश की जनता पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स कम करने की लंबे समय से मांग कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपनी प्राथमिकता बता दिए। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति के कारण एक ही दुकान पर देसी और विदेशी शराब बिकेगी। यहां तक कि महानगरों में सुपर बाजार में शराब मिलेगी। सरकार की तरफसे एयरपोर्ट पर शराब उपलब्ध कराई जाएगी। लोग अपने घरों में बीयर बार खोल सकते हैं। नई आबकारी नीति में शराब के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने व शराब की बिक्री बढ़ाने वाले कई निर्णय लिए गए है।

ओबीसी आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ बंद

भोपाल।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में चल रहे केस को क्लोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब चुनाव निरस्त हो गए हैं तो उसमें आरक्षण का विवाद ही नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के स्थानीय चुनाव के मामले में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मामले में सुनवाई बंद कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि, अब जबकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। तब इस मामले में सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि, भविष्य में वह जब भी चुनाव कराएगा तो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करेगा।

उल्लेखनीय है कि, कांग्रेस पार्टी की परिसीमन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए चुनाव आयोग को आदेशित किया था कि, सभी सीटों को सामान्य मानते हुए नए सिरे से अधिसूचना जारी करें और चुनाव संपन्न कराएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की थी।

सपा ने दंगाइयों को दिए टिकट- योगी आदित्यनाथ

लखनऊ।

यूपी विधानसभा चुनाव में सरगर्मी बढ़ने के साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, समाजवादी पार्टी ने यूपी में दंगाइयों को टिकट दिए हैं। सपा का टिकट पाने वालों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें कई सारे जाने-पहचाने दंगाइयों के नाम साफपढ़ने को मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। सीएम ने कहा कि, पहले यूपी में दंगे होते थे, वंशवादी राजनीति होती थी। अब उन सब पर रोक लग गई है, अब यूपी में केवल विकास की बात होती है और किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा ने वर्ष 2017 में सत्ता में आने से पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश में उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति थी। इस राजनीति को बढ़ावा देकर वे लोग गरीब किसानों और आम लोगों का शोषण कर रहे थे। हर तीसरे दिन प्रदेश में दंगा होता था। इसके चलते विकास के पहिए थमे हुए थे।

गोवा में अमित पालेकर को आप ने मुख्यमंत्री उम्मीद्वार किया घोषित

पणजी।

विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए अमित पालेकर को अपना सीएम फेस घोषित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यह घोषणा की। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले वर्ष आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी।

पालेकर ओबीसी में आने वाले भंडारी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी गोवा की कुल आबादी में करीब 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ओल्ड गोवा हेरिटेज साइट पर अवैध निर्माण के विरोध में भूख हड़ताल को लेकर पालेकर चर्चा में आए थे। पिछले वर्ष अक्टूबर में आप में शामिल हुए पालेकर ने पणजी में एक समारोह में सीएम फेस की घोषणा के बाद केजरीवाल को गले लगाया। इस मौके पर आप विधायक आतिशी भी मौजूद थीं।

आप संयोजक केजरीवाल ने ट्विटर पर साझा किए गए वीडियो में कहा, गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं, मौजदा पार्टियों और नेताओं से लोग तंग आ गए हैं। कुछ नेताओं ने गोवा की राजनीति पर कब्जा किया हुआ है। पैसे से सत्ता और सत्ता से खूब पैसा कमाते हैं, उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है गोवा बदलाव चाह रहा है।

स्व. श्री यशवंत घोड़ावत जी की पुण्यतिथि पर पत्रकार महासम्मेलन आज

जिले के गांव-गांव से पत्रकार पहुंचेंगे मेघनगर

माही की गूंज, झाबुआ।

पत्रकार जगत के हस्ताक्षर व माही की गूंज के प्रेरणा स्त्रोत स्व. श्री यशवंत जी घोड़ावत की 20 जनवरी को पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पत्रकार महासम्मेलन इस वर्ष जिला पत्रकार संघ के नेतृत्व में मेघनगर में पत्रकार संघ मेघनगर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री यशवंत जी घोड़ावत की ये 8 वीं पुण्यतिथि है और हर वर्ष जिला पत्रकार संघ द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन आयोजित होता आ रहा है। मेघनगर में होने वाले पत्रकार महासम्मेलन में इस बार अतिथि के रूप में सम्माननीय पद्मश्री श्री महेश जी शर्मा, कलेक्टर झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, शिक्षाविद् श्री पारस सकलेचा रतलाम, साहित्यकार श्री आशीष दशोत्तर रतलाम, अध्यक्ष एआईएम श्री अजयवीरसिंह मेघनगर, समाजसेवी श्री विनोद बाफना मेघनगर, समाजसेवी श्री सुरेशचंद्र जैन मेघनगर, थांदला विधायक श्री वीरसिंह भूरिया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश सोनी ने जिले के पत्रकारों को उक्त आयोजन में आने का आह्वान किया है। मेघनगर पत्रकार संघ के वरिष्ठ पत्रकार मोहन संघवी व राजेश सोनगरा ने बताया कि, कार्यक्रम की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और ग्रामीण पत्रकारिता के लिए विशेष योगदान देने वाले और कार्य करने वाले विरलय पत्रकार और कलम के धनी स्व. श्री यशवंत जी घोड़ावत की पुण्यतिथि पर जिले भर के पत्रकार आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पधार कर दादा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर पत्रकारों के सम्मान के साथ प्रतिभा एवं सरहानिय कार्य करने वाले महाअनुभवो का सम्मान भी जिला पत्रकार संघ एवं ईकाई मेघनगर द्वारा किया जाएगा। उक्त आयोजन कोरोना गाईडलाईन के साथ आयोजित किया जाएगा। पत्रकार संघ ईकाई मेघनगर के आयोजक समिति के पत्रकार सुभाष गेहलोत, लाखनसिंह देवाणा, दीपक व्यास, लोहित झामर, जयेश झामर, संदीप खत्री, सौरभ खेमसरा, मनीष नाहटा, संदीप जैन, रितिक शर्मा, देवेन्द्र जैन, निमिष नाहटा, मनोहर ठाकूर, अजय डामोर, चिनू देवाणा, महेश जोशी, निलेश कोठारी आदि सभी पत्रकारो न झाबुआ जिले के सभी पत्रकारों को उक्त पत्रकार महासम्मेलन मे पधार कर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

ईवीएम को लेकर मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।

ईवीएम मशीनों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से मतदान के खिलाफयाचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि, क्या अब उनको ईवीएम मशीन से दिक्कत है? शर्मा ने कहा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि, विधानसभा चुनावों से पहले सुनवाई हो। इस पर सीजेआई ने कहा कि, वो देखेंगे। शर्मा ने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61(अ) को चुनौती दी है, जिसमें बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया है। शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा इसके जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।

सांसद-मंत्री समेत कोरोना का आंकड़ा साढ़े सात हजार पार

भोपाल। फरवरी 2022 से पहले मध्य प्रदेश में हालात भयावह हो चले है। एक्टिव केसों की संख्या 43 हजार के पार हो गई है। बुधवार को 7 हजार 597 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है और 3 हजार 69 मरीज डिस्चार्ज हुए है, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 43 हजार 973 हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटि दर 9.81 प्रतिशत पहुंच गई है। बुधवार को इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कुल 5 मौते हुई है।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7 हजार 597 नए केस आए हैं। जिनमें 116 पुलिसकर्मी शामिल हैं। 7 हजार 597 नए केसों में इंदौर में 2 हजार 47, भोपाल में एक हजार 341, ग्वालियर में 642, जबलपुर में 514, उज्जैन 215, रतलाम 118, सीहोर 185, खरगोन में 122, शिवपुरी में 170, बड़वानी में 109 बाकी अन्य जिलों में 100 के अंदर केस मिले है। वर्तमान में भोपाल में 8 हजार 31 और इंदौर में 13 हजार 368 एक्टिव केस है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और उनकी पत्नी भी संक्रमित हो गए है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी पॉजिटिव आए है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, मंत्रीगण कोरोना से बचाव, उपचार और प्रबंधन के कार्यों एवं अधो-संरचनात्मक व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लेते रहे। होम आइसोलेशन व्यवस्था पर भी मंत्री एवं अन्य जन-प्रतिनिधि नजर रखें। यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी दूरभाष पर ली जाए। अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहें। कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण की स्थिति पर निगाह रखते हुए आर्थिक गतिविधियाँ पूरी सावधानियों के साथ संचालित की जाएँ।

रंभापुर में 8 वां कवि सम्मेलन हुआ सम्पन्न

एक लड़की में मुझको पूरा हिन्दुस्तान दिखा- कवि पंकज अंगार

माही की गूंज, मेघनगर/रम्भापुर।

गुजरात की सीमा से सटे ग्राम रम्भापुर में पत्रकार संघ रम्भापुर व ग्राम मित्र मंडल के संयोजन में छटवा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कोराना प्रोटोकाल के मापदंड व तय समय सीमा अनुसार रविवार को संपन्न हुआ। भुपेंद्र बरमंडलिया, अभय जैन, पंकज रांका के संयूक्त तारतम्य संयोजन में इस कवि सम्मेलन ने साहित्य का संचार व तनावपूर्ण माहोल से आमजन को मुक्त रखने के लिए हास्य लाफ्टर से हर कोई रसावादित हुए। आयोजन के दौरान कवियों व कोरोना काल में बेहतर सेवा देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। साहित्यिक गतिविधियां संचालित करने वाले जिले में ऐसे आयोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माहीं की गूंज के प्रधान संपादक संजय भटेवरा एवं संयोजन समिति के सदस्यो ने कवियों को माही की गूंज परिवार के स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। कवियों का परिचय सूत्रधार निसार पठान रम्भापुरी ने कराया।

चल मेरे साजन नदियां के पार, छुट्टी का दिन भी हैं इंतवार-राणा तबस्सुम

जुलफै उसकी नैनीताल सी भुजाओं में राजस्थान दिखा। एक लड़की में मुझको पूरा हिन्दुस्तान दिखा, पंकज अंगार ललित पुर उतरपदेश। खुशियों का सारा जहां होती है मां, मां तों केवल मां होती है,? एकता भारती पीलीभीत उत्तर प्रदेश। न पिये तों तबियत खराब होती हैं पी लेते हैं तों नियत खराब होती है, यार अजीब चीज है शराब एक दिन पिते एक दिन नहीं पीते, न नियत खराब होती न तबियत ख़राब होती, संचालक अशोक भाटी उज्जैन। न मचलता यौवन न कंगन पायल का अरमान लिखा, मैंने तो समस्या से पिडित जन-जन का हिंदुस्तान लिखा, निसार पठान रम्भापुरी।

लाफ्टर कवि मुंबई से आएं सुनील व्यास मुन्ना बैटरी ने हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया। कोमल नाजुक की कोमल श्रंगारित मुक्तकों सहित संचालन अशोक भाटी की शाब्दिक जुगलबंदी व देशी तड़क कवि हास्य के नाम से जाने-जाने वाले मांडव नालछा, धीरज शर्मा ने मालवी हास्य सहित व्यंग कविता व अपनी अद्भुत शैली का जलवा दिखाया। कवि सम्मेलन सुपर स्टार कवि जिन्हें सर्वाधिक माला मिली, पंकज अंगार, मुन्ना बैटरी, निसार पठान रहें। एकता भारती के गीतों की अगले वर्ष की चातकी प्यास की प्रतिक्षा अशोक भाटी का अद्भुत काव्य कौशल चिड़िया राम सनातन, द्वारका के धीश कृष्ण के पैरों में छाले कविता ने आध्यात्मिक संचार किया।

आयोजन में बतोर अतिथि डाक्टर बसंत सिंह खतेडिया, रोटरी क्लब के अध्यक्ष निलेश भानपुरिया, पत्रकार संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय भटेवरा, उद्योग पति विनोद बाफना, शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, शशांक तिवारी लोक गायक, डाक्टर योगेश नायक, रविन्द्र रांका, प्रवीण कटोता, दशरथ सिंह कठठा, सुनील डाबी, उर्स कमेंटी के अब्दुल कादिर भूरू भाई, राणापुर की लोक संस्कृति की लेखिका रेखा भूरिया, राजेश भंडारी, चंद्रशेखर जैन, प्रहलाद नायक, सरपंच बाबू गणावा, उपसरपंच सुरेन्द्र पड़वार, भरत मिस्त्री, विनम्र बाफ्ना भी उपस्थित थे। राम कविता में ज़िले व संभाग स्तर पर प्रथम रहें कवि संगम की प्रतियोगिता में गांव के ब्रजेश हाडा को भी सम्मानित किया। आयोजन को सफ्ल बनाने में भूपेंद्र बरमडलिया, पंकज रांका की टीम के साथ रविन्द्र बरमडलिया, ऋषि राका, भारत हाडा, विश्वास जोशी, माधव जोशी, समीर पठान, दीपक जैन आदि का सहयोग रहा। ?आयोजन में शूरूवाती संचालन मनीष गिरधाणी ने, आभार पंकज राका ने माना।

नुक्कड़ नाटक के साथ किया लोगों को जागरूक

माही की गूंज, सारंगी । संजय उपाध्याय

भारत माता संकुल संगठन बरवेट के सहयोग से ग्राम पंचायत बरवेट स्कूल मैदान में युवा कंपास हब द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक में युवाओं द्वारा रोजगार पंचायत, ग्राम सभा में किस प्रकार से समस्याओं और मुद्दों को लिखवाना और लिखे जाते हैं, इसके लिए जागरूक किया गया। शिक्षा में बालक-बालिकाओं को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए जागरूक किया गया। स्वास्थ्य में गर्भवती और छोटे बच्चों को समय-समय पर टीका लगवाने और नहीं लगवाने पर किस प्रकार की समस्याएं आती है के लिए जागरूक किया गया। भीड़ वाले स्थानों पर दूरी बनाए रखने, दो गज की दूरी और मास्क का उपयोग करने के लिए जागरूकता का संदेश प्रदान किया गया। कार्यक्रम में संकुल पदाधिकारी अध्यक्ष सविता मैड़ा, शांति गढ़वाल, सुगन मैड़ा साथ ही जनपद पंचायत से पंचायत इस्पेक्टर ज्ञान सिंह चौहान, पंचायत सचिव कैलाश भाबर, टीआरआईएफ पंचायत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नेहा छाबड़ा और ऑपरेटर साक्षी दीदी एवं समस्त हब और संकुल की टीम ने सहयोग किया। जिसमें ग्रामीणों और ग्रामवासियों को जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे कार्यक्रमों लोगो को जागरूक करने में काफी मददगार साबित हो रहे है, जिसमें न केवल मनोरंजन बल्कि जागरूकता का संदेश बहुत अच्छी तरह से ग्राम वासियों और शहर निवासियों तक पहुंचाया जा रहा।

माहेश्वरी समाज ने मनाया हल्दी-कुमकुम एवं नववर्ष मिलन समारोह

विभिन्न प्रतियोगिता एवं भजन-किर्तन का किया गया अयोजन

माहेश्वरी समाज महिला मंडल ने किया हल्दी कुमकुम एवं नववर्ष मिलन समारोह।

माही की गूंज, झाबुआ। माहेश्वरी समाज महिला मंडल झाबुआ द्वारा हल्दी कुमकुम एवं नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन स्थानीय माहेश्वरी लक्ष्मीनाथ मंदिर पर किया गया।

जिसमें महिलाओं ने एक.दूसरे को हल्की.कुमकुम का तिलक लगाकर सुहाग की सामग्री भेंट की गई। इस दौरान सभी के लिए एक मिनिट प्रतियोगिता के साथ भजन.किर्तन भी किए गए। संपूर्ण कार्यक्रम में महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती किरण माहेश्वरीए रेखा माहेश्वरीए अर्चना माहेश्वरीए कृष्णा कोठारीए अंजु सोनीए मीना सोनीए विनीता माहेश्वरीए ऋतु सोडानीए सुनिता अजमेराए भारती बांगड़ए रिया माहेश्वरीए आरती बांगड़ए मधु बांगड़ए रीना बांगड़ए नीता अजमेराए विजय बजाजए मेघा बांगड़ए पूनम आचार्य उपस्थित थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर का शांतिवन आबू से सुबह 10 बजे से ऑनलाईन राष्ट्रीय उद्घाटन करेंगे

संस्थापक प्रजापिता ब्रम्हाजी के 53वें आरोहण पर होगा यह राष्ट्र स्तरीय आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जनवरीए गुरूवार को सुबह 10ण्30 बजे से ब्रम्हकुमारिज के डायमंड हॉल शांतिवन आबू रोड़ में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोजेक्ट का ऑनलाईन द्वारा राष्ट्रीय उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट ब्रम्हकुमारी मुख्यालय माउंट आबू एवं भारत सरकार के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को ब्रम्हकुमारिज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रम्हाजी के 53वें अव्यक्त आरोहण के अवसर पर लांच किया जा रहा है।

20 जनवरी को ष्आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओरष् का होगा राष्ट्रीय ऑनलाईन उद्घाटन।

जानकारी देते हुए प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोपालपुरा संस्था की बीके जयंती दीदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे वर्षभर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जिनमें मेरा भारत .स्वस्थ भारतए आत्मनिर्भर किसान अभियान एवं महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री मोदी अगले 12 महीनों में होने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाएंगेए जिनमें मुख्य रूप से शांति की शक्ति युवा प्रदर्शनीए बस अभियानए अनदेखा भारतए एक भारत.श्रेष्ठ भारत और सड़क सुरक्षा मोटर बाईक अभियानए स्वच्छ भारत अभियान सम्मिलित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा महोत्सव के उपलक्ष में ग्रेमी अवार्ड विनर रिकी केज द्वारा बनाए हुए म्यूजिक एलबम को भी रिलीज करेंगे।

इनका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा

इस ऑनलाईन राष्ट्रीय आयोजन को भारत सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जीण् किशन रेड्डीए राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा एवं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी संबोधित करेंगे। साथ ही न्यूयार्क से ब्रम्हकुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी भी देश.विदेश से जुड़े भाई.बहनों को ईश्वरीय संदेश देकर राजयोग की अनुभूति करवाएंगी। यह महोत्सव संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी के सानिध्य में होगा।

जिले में भी देखा जाएगा प्रसारण

बीके ज्योति दीदी ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय आयोजन का देश.विदेशों के साथ झाबुआ जिले में भी ब्रम्हकुमारिज संस्था के सभी केंद्रों पर लाईव प्रसारण देखा जाएगा। जिला मुख्यालय झाबुआ पर समीपस्थ गोपालपुरा स्थित शिव स्मृति भवनए प्रजापिता संस्था पर भी लाईव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। बीके जयंती दीदी एवं ज्योति दीदी ने समस्त जिलेवासियों से ब्रम्हकुमारी संस्था पर उपस्थित होकर इस आयोजन को अधिकाधिक संख्या में देखकर लाभ लेने की अपील की है।

खनिज एवं राजस्व विभाग की कार्यवाही में रेत के 2 डंपर जप्त

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश एवं खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देशन में सहायक खनि अधिकारी राकेश कुमार कनेरिया के नेतृत्व में खनिजों के अवैध उत्खनन,परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा जिले की राणापुर तहसील व निकटवर्ती पारा के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन में संलिप्त वाहनों की जांच की गई। अलसुबह चली कार्यवाही में जिले के सीमांत इलाकों पारा तथा राणापुर में जांच के दौरान रेत का परिवहन करते दो डंपरों की जांच की गई। वाहन क्रमांक क्रमशः एमपी 09 केसी 8368 और एमपी 11 एच 6111 के चालकों से खनिज के परिवहन की वैधानिक रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज परिवहन हेतु आवश्यक वैधानिक दस्तावेज न पाते हुए, वाहनों को मौके से जप्त किया गया।दोनो जप्तशुदा वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त चौकी प्रभारी पारा की अभिरक्षा में रखा गया है। जब्तशुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तड़के चली इस कार्यवाही में मुख्य रूप से माइनिंग इंस्पेक्टर शंकर कनेश एवं तहसीलदार सुखदेव डावर सम्मिलित रहे।

बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने आकस्मिक रूप से शहर का भ्रमण किया

माही की गूंज, झाबुआ।

झाबुआ शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने आकस्मिक रूप से शहर का भ्रमण किया। जिसमें बस स्टेशन खड़ी वाहनों में मास्क नहीं लगाने वाला को समझाइश दी और चेतावनी भी दी। इसके पश्चात बस स्टेशन पर अव्यवस्थित रूप से खड़ी ठेला गाड़ी को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए। बस स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में लाइट लगाए जाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद नगर पालिका स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया और नगरपालिका के बाहर रैन बसेरा का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात एम-2 के समीप बन रही नवीन पुलिया का भी अवलोकन किया। निर्धारित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था और कंबल की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक आयोजित

माही की गूंज, झाबुआ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमिशनर कलेक्टर आदि की आयोजित होने वाली आगामी विडियों कान्फ्रेंसिंग के संबंध में मंगलवार को सांय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें विभागों से संबंधित बिन्दुओं पर समीक्षा की गई। जिसमें नगरिय निकाय के कार्यो, जल जीवन मिशन के कार्यो, कृषि विकास के कार्यो, खाद्यान वितरण के कार्यो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यो एवं कुपोषण से मुक्ति के लिए किए गए प्रयास, खनिज माफिया, भू- माफिया, आबकारी माफिया आदि विषयों पर यह समीक्षा बैठक आयोजित थी। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा विभागवार वन टु वन चर्चा की गई।

धर्मांतरण के नाम पर हिन्दू संगठनों द्वारा इसाई समाज को लगातार जबरन किया जा रहा बदनाम एवं परेशान

इसाई समाज की ओर से संपूर्ण जिले में तहसील स्तरों पर ज्ञापन सौंपकर ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की गई

माही की गूंज, झाबुआ।

इसाई समुदाय को धर्मांतरण के नाम पर पिछले कुछ महीनों से लगातार कुछ हिन्दू संगठनों द्वारा बदनाम कर सोशल मीडिया पर व्हाट्स.एपए फेसबुक पर गलत एवं आपत्तिनक पोस्ट डाली जा रहीं है। जिसके माध्यम से उक्त समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रहीं है। जिसको लेकर 19 जनवरीए बुधवार को संपूर्ण जिले में तहसील स्तरों पर इसाई समाज की ओर से प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया।

जिला मुख्यालय झाबुआ पर भी महामहिम राष्ट्रपतिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्लीए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगए महामहिम राज्यपाल मप्र एवं मप्र के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सोमेश मिश्रा को ज्ञापन प्रेषित कर समाजजनों की ओर से कहा गया कि पिछले कुछ महीनों से जिले में लगातार कुछ हिन्दू संगठनों द्वारा समाजजनों एवं समाज के धर्मगुरूजों के रूप में फादर एवं पास्टर पर झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके खिलाफपुलिस थाने पर झूठी शिकायते एवं अपराद्ध पंजीबद्ध करवाए जा रहे है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी समाज के विरूद्ध लगातार वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है।

प्रत्येक धर्म को प्रचार-प्रसार का अधिकार

जो समाज की स्वतंत्रता का हनन होकर संविधान में दिए गए सभी धर्मों के अपने.अपने प्रचार.प्रसार करने के अधिकार के विपरित है। मप्र में धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम.2020 लागू होने के बाद इस तरह के मामले काफी बढ़े है। ऐसे मामलों में इन संगठनों को प्रशासन एवं पुलिस भी मद्द करते हुए उक्त समाज के धर्म गुरूजों पर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे है।

झूठी एवं भ्रामक पोस्ट पर लगाई जाए रोक

कलेक्टोरेट ज्ञापन देने आए इसाई संप्रदाय के लोग।

ज्ञापनों में आगे मांग की गई कि समाज के विरोध में की जा रही ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाए जाने के साथ ही सोशल मीडिया पर इसाई समुदाय के विरूद्ध जो आपत्तिजनक पोस्ट एवं टिप्पणीयां की जा रही है। उस पर भी तत्काल रोक लगाकर ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

युवाओं को यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग सुविधा का जायजा लेने पहुचें कलेक्टर

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा बुधवार अपरान्ह शासकीय आदर्श महाविद्यालय झाबुआ पहुचें। यहां पर संकल्प कोचिंग क्लासेस जिसमें यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इन कक्षाओं का जायजा लिया। यहां पर लायब्रेरी के लिए पृथक से एक निर्धारित स्थल को चिन्हांकित किया। विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए एवं यूपीएससी एवं एमपीपीएससी के विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों का संग्रह यहां पर प्रदान किया। कलेक्टर द्वारा अध्ययनरत छात्रों से रूबरू चर्चा की एवं यहां पर प्रदान कि जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। इस दौरान गैर शैक्षणिक संस्थाओं के जिला संयोजक ओम शर्मा, शारदा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की प्रमुख किरण शर्मा, शासकीय आदर्श महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.सी.जैन, प्रो. कुवरसिंह चौहान, डॉ. राजू बघेल, प्रो. पंकज बारिया, प्रो. धुलसिंह खरत, डॉ. राज चंदेल्कर, प्रो. मुकेश बघेल आदि उपस्थित थे।

चोरी के बाद पुलिस से प्रताड़ित पीड़ित, दसों चक्कर लगाने के बाद भी नही दर्ज की एफआईआर

वाहः पुलिस का अजब सवाल... तुम चोर का नाम बताओ तो हम पकड़ेंगे चोर?

चौकी प्रभारी ने कहा चोर पकड़ कर माल दिलवा देंगे रिपोर्ट मत करो, कही भी शिकायत कर दो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा

माही की गूंज , पेटलावद/सारंगी।

अपनी सिविल को अच्छा बनाए रखने के लिए पुलिस ऐसे हथकंडों का उपयोग करती हैं जिससे उनके कार्यकाल में अपराध की स्थिति न के बराबर हो, जिससे आगे नोकरी में मिलने वाले प्रोमोशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही हो। लेकिन जिस चौकी प्रभारी की नाक के नीचे उसी के चौकी में पदस्थ उप निरीक्षक के चौकी के पास बने सरकारी क्वाटर से चोर लाखों का माल उड़ाकर ले जाए उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल वैसे ही खड़े हो रहे हैं। अब साहब अपनी बची-कूची इज्जत बचाने के लिए चौकी क्षेत्र में होने वाले अपराधो को रिकार्ड से बहार सुलटाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का झूठा झांसा देकर अपराध दर्ज नही कर रहे हैं।

मामला सारंगी चौकी का, जहां पदस्थ चौकी प्रभारी अशोक बघेल ग्राम छायन पूर्व में बलवंत सिंह राठौर के खेत पर 25 अक्टूम्बर 2021 को हुई चोरी का है, जिसका आवेंदन चौकी पर अगले ही दिन दिया गया। बलवंत सिंह ने बताया कि, उनके खेत में पानी की मोटर, केबल, स्टार्टर, पाइप सहित खेत पर खड़ी जुगाड़ का सामान लगभग एक लाख रुपये का माल चोरी कर गए। मामले की जानकारी लिखित में दी गई जिस पर पुलिस द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नही किया, तो दोबारा 30 अक्टूम्बर को शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने अपराध दर्ज नही किया न ही कोई जांच की।

दस बार चौकी के लगा दिए चक्कर, चौकी प्रभारी ने कहा चोर पकड कर सामान दिला देगे

किसी भी अपराध के दर्ज होने के बाद पुलिस पर उसको ट्रेस करने का दबाव बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस छोटे-मोटे अपराध दर्ज करती ही नही जिससे पीड़ितों को कभी चोरी गया सामान ही वापस नही मिलता। बलवंत सिंह के खेत पर चोरी होने के बाद लगभग दस से ग्याहरा बार चौकी पर एफ्आईआर करवाने के लिए जा चुके हैं, लेकिन चौकी प्रभारी अशोक बघेल ने मामला दर्ज करने की बजाए पीड़ित को चोरो को पकड़कर माल वापस दिलवाने की बात कहकर एफ्आईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इतना ही नही बार-बार फरियादी के चौकी पर जाने पर चौकी प्रभारी इतने गुस्से में आ गए कि, फरियादी को कहने लगे कि चोरो के नाम बताओ तभी कार्रवाई की जाएगी। बलवंत सिंह ने बताया कि, चौकी प्रभारी ने उसे धमकाते हुए कहा कि, कही भी शिकायत कर दो मेरा कुछ नही बिगड़ने वाला और कोई प्रकरण दर्ज नही होगा जब चोर पकड़गे तुम्हारा सामान दिला देगे।

सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत

फरियादी बलवंत सिंह राठौर के साथ चौकी सारंगी के प्रभारी द्वारा किए व्यवहार और मामला दर्ज नही करने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की है, जहॉ उन्होंने चोरी की घटना के बाद मामला दर्ज नही होने और पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसका शिकायत क्रमांक 16435146 दिया गया है। शिकायत के बाद फरियादी को विश्वास है कि, पुलिस चोरी का प्रकरण दर्ज कर चोरो को पकड़ेगी।

मोटर ,केबल, पाइप सहित खेत पर रखी जुगाड़ में लगा सारा सामान चुरा ले गए चोर।

बलवंत सिंह ने बताया कि, मामले की शिकायत पेटलावद एसडीओपी को भी लिखित में कर कार्रवाई की मांग करूंगा।

कारस्तानीः छत निलाम कर अपनों को कर रही उपकृत नगर परिषद

माही की गूंज, थांदला।

पिपली चौराहा पर स्थित दुकानो की छत

प्रदेश सरकार गरीब तबकों के उत्थान हेतु नित्य नई योजनाएं क्रियान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, किंतु नगर परिषद में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व कर्मचारी आपस में सांठगांठ कर नगर के पीपली चौराहा वार्ड क्रं. 7 वन विभाग के सामने व वार्ड 1 व बेढ़ावा बस स्टैंड वार्ड 15 पर निर्मित दुकानों की छतों को नीलाम करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मामले की तह तक जाने पर पता चला कि, आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिषद पर करोड़ों रुपये की देनदारी है। जिसके चलते नियमों को ताक में रखकर अपने चहेतों को उपकृत कर दुकानों की छत नीलाम करने पर तुली हुई है। जबकी पिपली चौराहे पर पार्किंग की समस्या अभी भी बनी हुई है, आवागमन घंटों जाम रहता है। इस संदर्भ में कलेक्टर को पत्र लिखकर नगर परिषद ने अपनी देनदारी का हवाला देकर तथा आरक्षण प्रक्रिया को ताक में रखकर अपने हाथों से उनकी पीठ थपथपाने का कार्य नगर परिषद कर रही है। विदित हो कि, उक्त परिषद के पदाधिकारी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करने में कुछ महाशय बचे हैं, जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ा कर अपने चहेतों को उपकृत कर नगर को विनाश की ओर ले जा रही है।

छत पर निलामी प्रक्रिया में कुछ सामाजिक, गैर राजनीतिक व जनहित में अपनी आवाज को मुखर करने वाले कुछ व्यक्तियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए परिषद के निर्णय को कलेक्टर को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त प्रक्रिया रोकने हेतु अनुरोध भी किया है, साथ ही उक्त प्रक्रिया रुकवाने हेतु विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेकर इसे न्यायालय में चुनौती देने का भी मन बना लिया है। वर्तमान में नगर परिषद पुराने नगर परिषद कार्यालय के समीप रहने वाले नालों पर नजूल की भूमि पर दुकान तानने के मामले में न्यायालय कार्रवाई के चलते उक्त दुकानों का मामला अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। केशव उद्यान के बगीचे में से परिषद ने नियम विरुद्ध रोड निकालकर कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के मामले में नगर परिषद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं साथ ही परिषद के सत्ताधारी व विरोधी दल के पार्षदों की चुप्पी उक्त मामले में समझ से परे हैं।

मास्क नहीं... हाट बाजार में भी उमड़ी भीड़

माही की गूंज, थांदला।

कोरोना की तीसरी लहर, आम जनों की लापरवाही का नतीजा ही कहा जाएगा कि, अतीत से भी हमने प्रेरणा नहीं ली है। दूसरी लहर में कई परिजनों के चिराग बुझकर परिवार को एक ऐसा जख्म दे गए हैं, जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता है। शासन की गाइडलाइन का पालन करना हर व्यक्तियों का दायित्व है किंतु अंचल में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार के दौरान भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हवा में उड़ गई। ग्रामीणों के साथ हाट बाजार में कई सामान विक्रेता भी बिना मास्क के सामान बेचते नजर आए, शायद यह प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी ही कही जाएगी। पुलिस विभाग दो पहिया वाहन चालकों को बिना मास्क के पाए जाने पर चालानी कार्यवाही मुस्तैदी से करता रहा। किंतु नगर में भारी भीड़ प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई, साथ ही आम जनों को भी चाहिए कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं करें व भीड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे वरना शासन व प्रशासन को भी बढतें संक्रमण को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मजबूरी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के साथ संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय होगा।

सरपंचों को वित्तीय अधिकार देने से नाराज़ हुए उम्मीदवार, प्रत्याशियों ने जताया विरोध

माही की गूंज, थांदला/पेटलावद।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जल्द करवाने ओर सरकार द्वारा पुराने सरपंच को फिर से आदेश देने के विरोध को लेकर सभी नए उम्मीदवार जैसे पंच, सरपंच, जनपद सदस्य उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार सभी ने मिलकर ग्राम पंचायत नौगांवा में हिंगलाज माता मंदिर पर बैठक रखी, जिसमें सभी नए उम्मीदवारो ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2014 में हुए थे अब तक 8 वर्ष होने के बाद भी मध्यप्रदेश सरकार चुनाव नहीं करा रही है। सरकार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा लेती है, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, और जीते हुए प्रत्याशियों को चार्ज वापस दे दिया गया। उनके कार्यकाल के 8 वर्ष होने आ गए लेकिन गांव का विकास जैसा था वैसा का वैसा जैसे पहले था। दो बार चुनाव की घोषणा कर दी, अबकी बार तो चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए और आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी, लेकिन फिर भी सरकार चुनाव नहीं करा पाई और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए। हम सभी नए प्रत्याशियों की यही मांग है कि, सरकार जल्द से जल्द या तो चुनाव कराए या फिर उन पुराने सभी जनप्रतिनिधियों को जो चार्ज दिया है वह सरकार उनसे वापस लेकर किसी वरिष्ठ कर्मचारी या नोडल अधिकारी या सचिव, सहायक सचिव को दे दिया जाए ताकि गांव का विकास हो सके। बैठक में विशेष चर्चा हुई जिसमें आगामी 21 जनवरी के दिन नई मंडी थांदला में सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उम्मीदवार बैठक में शामिल होंगे, वहां से पूरी रूपरेखा तैयार होगी। प्रत्याशी गणों ने यह भी कहा कि, हम किसी एक पार्टी या पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं हम सर्व नए प्रत्याशियों के साथ मिलकर हमारा अधिकार मांगेंगे, जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराएंगे..! कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बैठक में सभी नए प्रत्याशी गण जिसमे अनिल सोलंकी, अकलेश रावत, गोपाल डामोर, भारत कटारा, सुरेश बिलवाल, प्रेमसिंह रावत, शैलेश भूरिया, मलजी मैड़ा, रामसिंग थंदार, विजय मोरी, रामला, वरसिंग मैंडा, राजेश डांगी, दिनेश बामनिया, हुरतान मैंड़ा आदि सभी नए प्रत्याशी उपस्थित हुए।

बामनिया पंचायत के पूर्व सरपंच ने गंभीर आरोप लगाकर दर्ज करवाई आपत्ति

पेटलावद विकास खण्ड में भी सरकार के इस निर्णय का विरोध होता देखा जा रहा है। मंगलवार को भद्रकाली मन्दिर पर चुनाव में उतरे प्रत्यशियों ने बैठक रखी और सरकार के सरपंचो को पुनः वित्तीय अधिकार देने के निर्णय का विरोध कर जल्द ही प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। स्थानीय स्तर पर भी विरोध शुरू हो गया है, ग्राम पंचायत बामनिया के पूर्व सरपंच, एडवोकेट और 2021 में चुनाव में प्रत्याशी रहे नंदलाल गामड़ ने कलेक्टर को आपत्ति दर्ज करवाते हुए बामनिया पंचायत का वित्तीय अधिकार सरपंच रामकन्या मखोड को दिए जाने का विरोध किया है। आपत्ति में नंदलाल गामड़ ने सरपंच रामकन्या मखोड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धारा 40 और धारा 92 में कार्यवाही प्रस्तावित है, ऐसे में सरपंच को वित्तीय अधिकार नही देना चाहिए। नंदलाल गामड़ ने कलेक्टर से मांग की है कि, ग्राम पंचायत के चुनाव में सात अभ्यर्थी मैदान में उतरे थे उनकी समिति का गठन कर ग्राम पंचायत के कार्यो को किया जाए।

महंत श्री काशिगीरी महाराज की पुण्यतिथि पर होंगे विशेष आयोजन

माही की गूंज, झकनावदा।

जिले का पर्यटन स्थल बन चुके सिंघेश्वर धाम पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। जिससे यहां होने वाले आयोजनों में भी लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। प्रतिवर्ष मनाई जाने वाली ब्रम्हलीन महंत श्री काशिगीरी महाराज की 19 वी पुण्यतिथि 22 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी इस अवसर पर मन्दिर परिसर में दो दिवसीय आयोजन रखा गया है। 21 जनवरी रात्रि को भजन संध्या और 22 जनवरी को रुद्र अभिषेक, हवन, पूर्णाहूती, महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते आयोजन को सीमित रखा गया हैं, जिसके चलते प्रतिवर्ष से कम भीड़ जुटेगी।

कोरोना गाइडलाइन का पालन नही करने पर हुई चालानी कार्यवाही

माही की गूंज, पारा।

जिले में कोरोना सवंमित के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भी नगरवासी बिना मास्क लगाए बेखौफहोकर घूम रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं। यही हाल वाहन चालकों व बस में बैठे यात्रियों को बिना मास्क लगाए देखा जा सकता है, इसके अलावा पारा नगर में दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते दिखाई दे रहे है। जिले में बढ़ते आंकड़ों के अनुसार नायब तहसीलदार रामा अपनी टीम के साथ वाहनों के चालकों जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उन लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई, इसी के साथ नायाब तहसीलदार द्वारा राहगीरों को कोरोना से बचने के लिए समझाइश दी जा रही है। नायब तहसीलदार बबली बर्थडे, मंत्री अमर सिंह मुजाल्दा, पटवारी नरेंद्र सांवरिया चौकीदारों के साथ नगर में चालानी कार्रवाई की।

सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क ...!

टेमरिया-करवड़ मार्ग की स्थिति हुई गंभीर, लोक निर्माण विभाग कुम्भकर्णी नींद में

आए दिन लोग हो रहे दुर्घटना का शिकार, राहगीर और वाहन चालक परेशान

माही की गूंज , पेटलावद। राकेश गेहलोत

बात मध्यप्रदेश की सड़कों की हो रही है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अमेरिका जैसे देश मे आकर मध्यप्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से अच्छी बताते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किए जा चुके हैं और लोगो ने उनके कॉमेडी वीडियो तक बना कर वायरल किए है। खेर जो भी हो मध्यप्रदेश की सड़कें भले ही अमेरिका के मुकाबले की नही हो लेकिन इतनी बुरी भी नही की उस पर चलना दुश्वार हो जाए, फिर भी कहा जाता है काम कितना भी अच्छा हो कोई न कोई कमी तो ऐसी रह ही जाती है कि, लोगो को कहना पड़ता है कि ÷मखमल के कार्पेट पर टाट का पैजमा÷ लगा दिया।

ऐसा ही एक मामला पेटलावद विकास खण्ड के 6 किलोमीटर के रोड में सामने आया, जहां मध्यप्रदेश सरकार के दावों को मुह चिढ़ाती नजर आ रही है। बात कर रहे हैं थांदला-बदनावर स्टेट हाइवे को रतलाम-झाबुआ मार्ग से जोड़ने वाले 6 किलोमीटर के टेमरिया से करवड़ मार्ग की जो वर्तमान में अपनी दुर्दशा पर आशु बहा रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालको और राहगीरों को पता तक नही लगता कि, सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क, मार्ग की हालत इतनी दयनीय हो चुकी हैं की इस पर वाहनों का तो ठीक पैदल चल पाना भी मुश्किल हो गया हैं।

लापरवाह लोग निर्माण विभाग की वजह से उठाना पड़ रहा है लोगो को नुकसान

कहने को तो सड़को के रख रखाव का जिम्मा लोकनिर्माण विभाग के पास है, लेकिन बदलते स्वरूप ओर नए रोडो के निर्माण का काम एमपीआरडीसी के सुपर्द किया जा चुका है। कम ही सड़के है जो अब लोक निर्माण विभाग के अंडर में रह गई हैं जिसमे से टेमरिया-करवड़ मार्ग भी एक है, लेकिन कम काम होंने के बाद भी लापरवाह विभाग के पास उक्त मार्ग को रिपेयरिंग करवाने का समय नही है, जिसका खामियांजा यहां से गुजरने वाले वाहन चालको और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है, जिनको आए दिन दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है।

वर्ष 2017-18 में बना था मार्ग 3 वर्ष भी नही चला, एक बार रिपेयरिंग तक टूट गई

मिली जानकारी अनुसार लोक निर्माण के द्वारा वर्ष 2017-18 में मार्ग बनाया गया था, लेकिन मार्ग का निर्माण इतना घटिया स्तर का हुआ की मार्ग दो वर्ष भी नही चल पाया और विभाग को इस मार्ग पर रिपेयरिंग तक करना पड़ गई, वो भी नही टिकी और निर्माण के तीन वर्ष बाद मार्ग की स्थिति जग जाहिर है और इस मार्ग पर रहने गुजरने वाले लोगो को मजबूरी में इस मार्ग का उपयोग कर अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है।

टेमरिया निवासी सुरेन्द सिंह बताते है कि, इस मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए और बड़े वाहनों के निकलने के दौरान धूल के गुब्बार उठ जाते हैं और कई बार छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त का शिकार तक हो जाते हैं। लोक निर्माण के जिम्मेदार अधिकारी पेटलावद एसडीओ रेशम गामड़ और विभाग के ई विजय सिंह पंवार के पास फोन उठाने तक का समय नही है।

करडावद-करवड़ मार्ग के निर्माण के कारण बड़ा आवागमन

थांदला-बदनावर मार्ग पर पहुँचने या रतलाम-झाबुआ मार्ग तक पहुँचने के लिए पेटलावद से कुछ दूरी पर दो मार्ग कटते है, एक करडावद से करवड़ ओर दूसरा टेमरिया से करवड़ वर्तमान में करडावद से करवड़ मार्ग का निर्माण विगत दो वर्ष से चल रहा है जो कि लंबा भी पड़ता है, ऐसे में टेमरिया-करवड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। लेकिन उक्त मार्ग की हालत खस्ता और खराब होने से रोड से वाहन भी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बंदरबाट और भ्रष्टाचार के कारण घटिया निर्माण का खामयाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वही क्षेत्र में विकास का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि और विपक्ष के नेता जनता से जुड़े मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है ।

संपादकीय

फिर पाक की बदनामी

पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की बानगी मीडिया के जरिए पेश की। एक अधिकारी द्वारा मीडिया को उपलब्ध यह जानकारी भू-आर्थिकी पर केंद्रित थी। फिर गत शुक्रवार को पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए। उल्लेखनीय है कि, यह जानकारी उस दिन सार्वजनिक हुई, जिस दिन पंजाब पुलिस ने भारत-पाक सीमा पर पांच किलो विध्वंसक आरडीएक्स बरामद किया। उससे कुछ दिन पहले कश्मीर में एक पाक आतंकवादी को मार गिराया गया था। बहरहाल, भारत की जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि, क्या पाक की कथित भू-आर्थिक धुरी में कश्मीर व पंजाब में लगातार जारी अलगाववादी नीतियों को त्यागा जाएगा...?

दरअसल, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाक लगातार भू-राजनीतिक समीकरणों के जरिए अपनी रक्षा क्षमताओं को उन्नत करता रहा है। फिलहाल भी रक्षा तैयारियों में संलिप्त है और समुद्री गतिविधियां भी बढ़ा रहा है। जाहिर है इन तैयारियों के केंद्र में भारत ही रहा है। इतना ही नहीं, जिस प्रतिगामी व खतरनाक विचारधारा को पाक में प्रश्रय दिया जाता रहा, वह भारत में हिंसक संघर्ष को ही बढ़ावा देती रही है। बहरहाल, अब जब पाक की अर्थव्यवस्था मरणासन्न अवस्था में है, तो अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना लाजिमी है। आज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसे ऋण देने में परहेज कर रही हैं। सर्वविदित है कि, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर खुद पाक का रवैया आक्रामक रहा है। इस आक्रामकता को कम करने के बजाय उलटे पाक भारत पर पूर्व की ओर कनेक्टिविटी को बंधक बनाने का आरोप लगाता रहा है। बहरहाल, वास्तविकता को सिर्फ बयानबाजी से नहीं झुठलाया जा सकता। यह दुनिया जानती है कि, भारत अफगानिस्तान में भूख से जूझते लोगों को खाद्यान्न भेजना चाह रहा है, लेकिन पाक ने अपनी सीमा से होकर सहायता सामग्री भेजने पर दो माह से फैसला नहीं लिया। साफ है कि, यदि पाक भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र बाजार के लिये अपने व्यवसायों के रास्ते बंद रखता है तो भू-आर्थिक नीति के लक्ष्य शायद ही पूरे हो पाएं।

नि:संदेह, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए सतत और समावेशी आर्थिक विकास की जरूरत होती है। उसके लिए उग्रवाद व संप्रदायवाद के खिलाफ संकल्प लेने की जरूरत है। शांति की स्थापना के बाद ही व्यापार-कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। एक तरफ कारोबार और दूसरी तरफ आईएसआई का वार, साथ-साथ नहीं चल सकता। बहरहाल, पाक ने अभी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, मगर आर्थिक संबंधों में सुधार विश्वास व सकारात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में जो बात उम्मीद जगाती है वह यह कि, पाक भारत के साथ आगामी सौ वर्षो तक शांति बनाए रखना चाहता है। इस पंचवर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत से रिश्ते सुधारने व व्यापार को बढ़ाने के साथ ही कश्मीर विवाद को किनारे रखने की बात भी सामने आती है। यानी सकारात्मक बातचीत के साथ सहयोग व व्यापार बढ़ाने की बात कही गई है। यदि पाक वाकई यह ईमानदारी से कह रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल, कहीं न कहीं पाक चीन की नीति का अनुसरण कर रहा है। वह यह कि भारत-चीन सीमा पर विवाद के साथ दोनों देशों का कारोबार सौ अरब डॉलर पार कर चुका है। चीन के साथ हालिया विवाद के बावजूद दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि ही हुई है। हालांकि, भारत पाक के रिश्तों में ज्यादा जटिलताएं हैं, उनका समाधान इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दोनों देश हमेशा के लिये युद्ध व टकराव के साथ आगे नही बढ़ सकते। भारत कई बार कह भी चुका है कि, घात व बात साथ-साथ नहीं चल सकते। इसके बावजूद पाक यदि कश्मीर में भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करके आगे बढ़ने को तैयार है तो उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। जो दक्षिण एशिया में शांति व तरक्की की जमीन तैयार कर सकता है। इससे जहां बेहद खस्ता हाल से गुजर रही पाक की अर्थव्यवस्था को प्राणवायु मिल सकेगी, वहीं भारतीय कारोबारियों को नया बाजार मिल सकेगा। नि:संदेह, सफल व्यापार के लिए विश्वास व शांति अपरिहार्य हैं।

नई तकनीक के साथ रोजगार संरक्षण

भरत झुनझुनवाला

तमाम वैश्विक आकलनों के अनुसार भारत विश्व की सबसे तेज आर्थिक विकास हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक सलाहकारी संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा है कि, 2050 में भारत चीन के बाद विश्व की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है यदि आर्थिक सुधारों को लागू किया जाए। सामान्य रूप से वैश्विक संस्थाओं का दबाव रहता है कि जीएसटी, बुनियादी संरचना, पूंजी के मुक्त आवागमन और मुक्त व्यापार जैसे सुधारों को लागू किया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि, इन्हीं सुधारों को लागू करने के बावजूद हमारी आर्थिक विकास दर पिछले छह वर्षों में लगातार गिर रही है। इसलिए इतना सही है कि हमें आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन यह सही नहीं कि इन्हीं आर्थिक सुधारों के सहारे हम आगे बढ़ सकेंगे। यहां विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास दर में गिरावट के विरोधाभास से भ्रमित नहीं होना चाहिए चूंकि हमारी कथित तेज विकास दर अंधों में काना राजा जैसी है।

सत्य यह है कि, हमारी आर्थिक विकास दर में गिरावट केवल आर्थिक नीतियों के बल पर नहीं संभल सकती है। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती नई तकनीकों से सामंजस्य बैठाने की है। सेंट स्टीफेंस यूनिवर्सिटी कनाडा के प्रोफेसर मैथ्यू जानसन ने कहा है कि, 2035 तक 50 प्रतिशत रोजगार का हनन हो जाएगा क्योंकि ये कार्य रोबोट द्वारा किए जायेंगे। भारत के लिए यह परिस्थिति विशेषकर दुरूह है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा हमारे श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यदि इन्हें आय अर्जित करने के समुचित अवसर नहीं मिलेंगे तो ये कुंठित होंगे और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर ने बताया कि, उनके एमए की डिग्री हासिल किए हुए छात्र एटीएम तोड़ने जैसी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं हैं। दूसरी तरफ केरल में एक रेस्तरां में एक रोबोट द्वारा भोजन परोसा जा रहा है और हमारी अपनी मेट्रो में भी बिना ड्राइवर की ट्रेन को चलाया गया है। इसलिए दो परस्पर विरोधी चाल हमारे सामने हैं। एक तरफनई तकनीकों के उपयोग से रोजगार का हनन हो रहा है तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

इस समस्या को और गंभीर बनाया है हमारी उन नीतियों ने, जिनमें छोटे उद्यमियों को बड़े उद्यमों से सीधे प्रतिस्पर्धा में खड़े होने के लिए कहा गया है। बड़े उद्योगों की उत्पादन लागत कम आती है। जैसे दवा का उत्पादन करने वाली बड़ी कम्पनी कच्चे माल को चीन से आयात करेगी, कंटेनर को ब्राजील से लाएगी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जर्मनी से आयात करेगी। इनके पास अच्छी गुणवत्ता के इंजीनियर होंगे। बड़े पैमाने पर भी उत्पादन करने से लागत कम आती है, जैसे घानी से तेल निकालने में लागत ज्यादा आती है जबकि एक्सपेलर में लागत कम आती है। इसलिए बड़े उद्योगों को बढ़ावा देकर हम सस्ते माल का उत्पादन अवश्य कर रहे हैं लेकिन इसमें रोजगार का हनन हो रहा है। हमारे सामने ही नहीं बल्कि विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम युवाओं को इस बदलते तकनीकी परिदृष्य में रोजगार उपलब्ध कराएं।

अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारी कम्पनी आर्थर डी लिटिल और बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि, स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन और छोटे उद्योगों को सहायता देनी चाहिए। लेकिन प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं होगा। कारण यह कि छोटे उद्यमी की उत्पादन लागत ज्यादा आयेगी ही। इन्हें कच्चा माल थोड़ी मात्रा में स्थानीय सप्लायर से खरीदना पड़ता है, तुलना में घटिया गुणवत्ता के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने पड़ते हैं, और एक ही व्यक्ति को उत्पादन, बैंक, खाता, श्रमिक, आदि सब काम देखने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों में इनकी कुशलता बड़ी कम्पनियों की तुलना में न्यून होती है। इस समस्या का समाधान भारत सरकार द्वारा छोटे उद्योगों के क्लस्टर बनाकर हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मनमोहन सिंह सरकार के समय एक कमेटी ने कहा था कि, छोटे उद्योगों का विशेष स्थानों पर एक झुंड बना दिया जाए जैसे मुरादाबाद में पीतल के सामान का और लुधियाना में होजरी का तो ये बड़े उद्योगों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। इनके कई कार्य सामूहिक स्तर पर किये जा सकते हैं जैसे कच्चे माल की गुणवत्ता की टेस्टिंग करना अथवा प्रदूषण नियन्त्रण के उपकरण सामूहिक रूप से स्थापित करना इत्यादि। लेकिन इस नीति के बावजूद अपने देश में छोटे उद्योग पिट रहे हैं और रोजगार की समस्या गहराती जा रही है। इसलिए केवल समर्थन की हवाई बातों को करने के स्थान पर हमें समझना होगा कि छोटे उद्योगों को यदि जीवित रखना है तो उन्हें वित्तीय सहायता देनी ही पड़ेगी।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि, छोटे उद्योगों द्वारा बनाये गये माल की लागत अधिक होगी। जैसे बड़े उद्योग में बनाई गई टीशर्ट 200 रुपए में उपलब्ध हो सकती है तो छोटे उद्योग द्वारा 250 रुपए में। इस ऊंचे मूल्य को उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। जो टीशर्ट हमें बड़ी कम्पनी से 200 रुपए में मिल सकती है उसे छोटे उद्योगों से उपभोक्ता को 250 रुपए में खरीदना होगा। प्रश्न है कि, ऐसा क्यों किया जाए? मेरा मानना है कि, हमें इस 50 रुपए के अतिरिक्त खर्च को 'रोजगार टैक्स' के रूप में देखना चाहिए।

हमारे सामने दो रास्ते हैं। यदि हम बड़े उद्योगों से उत्पादन करायेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, बेरोजगारी भत्ता देना होगा और अपराध से भी आर्थिक विकास का ह्रास होगा। इन बेरोजगारी भत्ते और अपराध के नियन्त्रण के मूल्य को यदि छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाए तो छोटे उद्योग चल निकलेंगे, उनके द्वारा रोजगार उत्पन्न होंगे और ये खर्च करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रश्न यह भी है कि, यदि हमारे देश में टीशर्ट के उत्पादन का मूल्य 250 रुपए है तो हम वैश्विक बाजार में निर्यात कैसे करेंगे? इसका उपाय है कि, निर्यात विशेष के लिए बड़े उद्योगों द्वारा सस्ते उत्पादन की छूट दे दी जाए लेकिन घरेलू बाजार के लिए छोटे उद्योगों से ही उत्पादन कराया जाए। ऐसा करने से हम वैश्विक बाजार के लिए रोबोट से उत्पादन कर सकते हैं और घरेलू बाजार के लिए श्रम से उत्पादन कर सकते हैं। हम दोनों उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं।

यूपी : भाजपा में भागदौड़

ओमप्रकाश मेहता

भारतीय राजनीति के मार्गदर्शक उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा में भागदौड़ का खेल शुरू हो गया है, मोदी-योगी की कथित 'दादागिरी' से उत्पीड़ित भाजपाजन अब दल को छोड़कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी का द्वार खटखटाने लगे है... और यह स्थिति सिर्फ उत्तरप्रदेश के सत्तारूढ़ दल के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे अहम् चुनावी राज्य पंजाब की भी है, जहां कांग्रेसजन भाजपा का द्वार खटखटा रहे हैं।

वैसे भारतीय प्रजातंत्र में दल बदल का यह चलन कोई नया नही है, यह तो कई वर्षो से चला आ रहा है, सत्तारूढ़ दल के नेता में जब अहम् की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर हर राजनीतिक दल के साथ यही होता आया है, जिसकी किरदार स्वयं इंदिरा गांधी भी रही है, किंतु इस बार केवल इतिहास ही नहीं दोहराया जा रहा है, बल्कि इतिहास में नए आयाम जोड़े जा रहे है, जो स्पष्ट करते है कि देश-प्रदेश के नेता कितने अहंकारी हो गए है? वैसे इस दल-बदल के दौर को हवा देने में सदा से उत्तरप्रदेश ही अग्रणी रहा है जिसका साथ अन्य कई राज्यों ने दिया है।

यदि हम ताजे दौर की बात करें तो उत्तरप्रदेश के एकमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे के साथ भाजपा से इस्तीफे का एलान किया है, श्री मौर्य उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता है और 2016 में बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी बेटी अभी भी भाजपा से सांसद है उत्तरप्रदेश पिछड़ा वर्ग में उनका काफी प्रभाव है तथा मौर्य के इस्तीफे को भाजपा के लिए काफी बड़ा झटका बताया जा रहा है। श्री मौर्य के साथ फिलहाल तीन भाजपा विधायकों ने भी इस्तीफें की पेशकश की है तथा राज्य के सभी कौनों ने उनके समर्थक भाजपा छोड़ सपा में जाने का एलान कर रहे है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने करीब बीस विधायकों के भाजपा छोड़ने की भविष्यवाणी की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की है, जबकि गोवा विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है। यद्यपि भाजपा छोड़ने वाले पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिलहाल यह औपचारिक घोषणा नहीं की है कि, वे किस पार्टी का दामन थामने जा रहे है, किंतु मंत्री पद तथा पार्टी छोड़ने के तत्काल बाद उनकी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई भेंट ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि उनका अगला राजनीतिक कदम सपा में ही होगा। पिछड़े वर्ग के इस वरिष्ठ नेता के सपा में प्रवेश को समाजवादी पार्टी नेता पार्टी के सुखद व शुभ बता रहे है तथा मान रहे है कि राज्य में अगली सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी तथा अखिलेश फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेगें? देश की राजनीतिक दिशा दिखाने वाले उत्तरप्रदेश के इस नए राजनीतिक घटनाक्रम ने जहां यह एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि, उत्तरप्रदेश के साथ ही देश के आम वोटरों का भी भाजपा से मोहभंग होने लगा है, वहीं प्रतिपक्षी दलों को भी अब यह एहसास होने लगा है कि, देश की सत्ता के सिंहासन से भाजपा को हटाना है तो मजबूत प्रतिपक्ष का होना जरूरी है और इसी बात को लेकर प्रतिपक्षी दलों में खुसर-फुसर शुरू हो गई है। कोई आश्चर्य नही होगा कि, उत्तरप्रदेश चुनाव के पूर्व ही प्रतिपक्षी दलों की एकता की नई रणनीति सबके सामने आ जाये?

इसीलिए इन घटनाक्रमों से ऐसा लगता है कि देश में नए राजनीतिक तूफान की शुरूआत भी उत्तरप्रदेश से ही होगी और सब के सामने योगी जी का चेहरा होगा, जबकि निशान सीधे मोदी जी पर होगा। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि, उत्तरप्रदेश के करीब एक सौ भाजपा विधायक एक जोरदार धमाके के माध्यम से मोदी को यह विस्फोटक संदेश देने वाले है। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का सवाल है उन्हें भाजपा में मोदी-शाह-नड्डा के बाद चौथे क्रम का सबसे बड़ा नेता माना जा रहा था। साथ ही जिन पांच राज्यों में अगले महीनें विधानसभा चुनाव होने जा रहे है, उनमें से चार राज्यों में वर्तमान में भाजपा की सरकारें है, सिर्फ पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार है। भाजपा को यह आशंका है कि, यदि उत्तरप्रदेश के राजनीतिक ग्रहण की काली छाया अन्य चुनावी राज्यों पर भी पड़ गई तो फिर पार्टी का क्या होगा? पार्टी ही नहीं संसद और विशेषकर राज्यसभा का क्या होगा? जहां आगामी छः महीनें बाद सतर से अधिक सीटों के चुनाव होने वाले है? इन्हीं सब तथ्यों को लेकर भाजपा की चिंताएं बढ़ गई है।

प्रतिपक्षी कह रहे है कि अभी तो यह देश की भावी राजनीतिक फिल्म का ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म तो किसी 'टैरर' फिल्म से कम नहीं होगी?

पाक की फितरत

सिद्धार्थ शंकर

सीमा पार से आतंकवाद फैलाने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई भारत विरोधी साजिश में नए रास्तों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की कवायद में जुटी है। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाक अब धर्म का रास्ता अख्तियार करने में जुटा है। करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ की आशंका भी खुफिया एजेंसियों ने जाहिर की है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा को सौंपी है। आईएसआई करतारपुर कॉरिडोर से आतंकियों को भारत भेजने के लिए दस्तावेज व सुविधाएं मुहैया कराएगी। खास मकसद के लिए आतंकियों को दो सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग आईएसआई की निगरानी में दी गई है। यह भी पता चला है कि आतंकी संगठन पांच लोगों के साथ ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, जो सिख पोशाक पहनेंगे। इस संगठन को साकरगढ़ में एक आतंकी शिविर में आईएसआई की निगरानी में दो सप्ताह का कमांडो प्रशिक्षण दिया गया है और यह लश्कर-ए-तंजीम संगठन से जुड़ा है। निकट भविष्य में घुसपैठ की यह कोशिश की जा सकती है। पाकिस्तान की तरफ से आतंक परस्त नीति अपनाए जाने की खबर आज पूरी दुनिया को है। यहां तक की जिस तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित करने में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से बदनामी मोल ली, उसी ने पाक को आंखें दिखा दी है। दरअसल, तालिबान इस बार अपनी आतंक वाली नीति को पीछे छोड़ना चाहता है, मगर पाक को इसी में अपना हित दिख रहा है। यही वजह है कि आज दोनों देशों में ठन गई है। आतंकवाद से जूझती दुनिया को राहत दिलाने या इसकी त्रासदी को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है कि इसके वित्तीय स्रोतों को रोका जाए। पिछले करीब दो दशक के बीच की घटनाओं के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर इसके लिए जिम्मेदार कारकों और वैसे पक्षों की पहचान की जा सकी है, जो परोक्ष रूप से आतंकी संगठनों को या तो वित्तीय मदद मुहैया कराते हैं या फिर इसे रोक पाने में नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है, जिसके बारे में विश्व समुदाय की यह धारणा बनी है कि वह आतंकवादी संगठनों को अलग-अलग स्रोतों से मिल रही वित्तीय मदद या उनकी गतिविधियों को रोक पाने में अपेक्षा के अनुरूप कामयाब नहीं हुआ है। दरअसल, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई किसी भी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है और इस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान ने ऐसे कदम नहीं उठाए हैं, जिसे आतंकवाद पर लगाम लगाने के मद्देनजर ठोस पहलकदमी कहा जाए। हालांकि पाकिस्तान के आम लोग यह जान-समझ रहे हैं कि विश्वव्यापी बदनामी के कारण दुनिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और खासकर उसकी सेना को शायद इसकी परवाह नहीं। हैरानी इस पर है कि क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान सच को स्वीकार करने के बजाय अपनी आतंकपरस्त सेना की कठपुतली बनना पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ओर खुद को आतंक पीड़ित बताता है और दूसरी ओर किस्म-किस्म के आतंकियों को पालने-पोसने का भी काम करता है। आतंक के रास्ते पर चलते रहने पर आमादा पाकिस्तान यही जाहिर कर रहा है कि वह अभी भारत समेत दुनिया के लिए सिरदर्द बना रहेगा। हालांकि दुनिया पाकिस्तान का रोना-धोना सुनना पसंद नहीं कर रही है, लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए भारत को उससे नए सिरे से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए। यह तैयारी निर्णायक ही होनी चाहिए। यह बेवजह नहीं है कि वैश्विक आतंकवाद पर नजर रखने वाले एक अंतरराष्ट्रीय मंच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की पिछली बैठक में एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे सूची में ही बनाए रखने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि एफएटीएफ ने अपने आकलन में उन सत्ताईस कार्ययोजनाओं में से छह को पूरा करने के मामले में पाकिस्तान को नाकाम पाया, जबकि इसे पूरा करने की समय-सीमा खत्म हो गई है। अब एफएटीएफ ने अगले साल यानी 2021 तक पाकिस्तान को सभी कार्ययोजनाओं को पूरा करने को कहा है। विडंबना यह है कि आतंकवाद का वित्तपोषण करने को लेकर लंबे समय से कठघरे में होने और सवाल उठाए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने इस मसले पर ऐसे कदम नहीं उठाए, जिससे विश्व समुदाय के बीच उसे लेकर कोई सकारात्मक धारणा बन सके। विचित्र है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ओर से लागू प्रतिबंधों का नुकसान समझता है, इसके दायरे से बाहर भी आना चाहता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना वह जरूरी नहीं मानता है। जबकि एफएटीएफ का मुख्य उद्देश्य ही विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने से रोकने के लिए नीतियां बनाना है। ऐसे में समझा जा सकता है कि एफएटीएफ के रूप में एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच ने पाकिस्तान को क्यों ग्रे सूची में बनाए रखा है। फिलहाल उसके लिए राहत की बात सिर्फ यह है कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया।

जीवन का अनुशासन देगा महामारी से मुक्ति

सुरेश सेठ

जिस तेजी से कोरोना की लहर देश में फैली है, उसने चकित किया है। कहां तो यह सोचा जा रहा था कि भारत में टीकाकरण की रिकॉर्ड सफलता के कारण, एक बरस में ही लोगों को डेढ़ सौ करोड़ टीका लग जाने के कारण कोरोना की तीसरी लहर का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का दबाव बीते वर्ष के पूर्वार्द्ध में बहुत कम हो गया था। सोचा जा रहा था कि, अब पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में कोरोना लहर के तीसरे चरण का संक्रामक, रुग्ण एवं मारक प्रभाव या तो होगा ही नहीं, यदि होगा भी तो बहुत हल्का और विलम्ब के साथ।

बीते वर्ष बेशक देश को कुछ खुले महीने मिल गए, जहां टीकाकरण का बोलबाला रहा और संक्रमण की दहला देने वाली खबरें कम होती चली गई। देश ने राहत की सांस ली थी। आम लोगों ने तो जैसे महामारी को अलविदा कह दिया। शारीरिक अंतर और मास्क पहनने को तिलांजलि देकर ये सब लोग आम दिनों की तरह पुनः अपने काम में जुट गये। परिणाम सबके सामने हैं। अपनी जिंदगी को पुनः पटरी पर लाने के लिये, किसान, उद्यमी, निवेशक और कामगार जुटे थे, अब उखड़ते नजर आ रहे हैं।

वैसे पिछले वर्ष के बीतने के साथ ही नए वर्ष के पहले पखवाड़े में न केवल केंद्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पुष्टि की कि देश के सात में से छह उत्पादन घटकों ने वर्ष 2020-21 में कोरोना पूर्व के स्तर को स्पर्श कर लिया। रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया कि, इस वर्ष देश आर्थिक विकास दर में वृद्धि करके 9.2 प्रतिशत प्राप्त कर लेगा, जबकि इससे पहले यह अनुमान 8.5 प्रतिशत का था। जहां तक इससे पिछले वर्ष का संबंध है, कोरोना की प्रथम लहर के प्रहार और एक पूर्ण बंद व एक अपूर्ण बंद के कारण यही आर्थिक विकास दर गिर कर शून्य से भी नीचे 7 प्रतिशत पर चली गई थी। सकल घरेलू उत्पाद भी कोरोना पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में बहुत नीचे चला गया था। नतीजा, बेकारी में बेतहाशा वृद्धि हुई जितनी देश ने पिछले पैंतालीस बरस में नहीं देखी थी और महंगाई का स्तर बढ़कर मनमोहन काल तक चला गया। इसी को नियंत्रित करने की घोषणा मोदी सरकार ने अपनी दूसरी शासन पारी में की थी।

केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक के इस विकास मूल्यांकन की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानक एजेंसियों ने भी कर दी है। वर्षांत के उत्सवों वाले चार महीनों में आम लोगों की ओर से बढ़ती डिमांड ने देश के बाजारों में मांग का अवसाद हर लिया। इससे पहले कोरोना की असाधारण परिस्थितियों में न तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक बूस्टर और न ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी रखी गयी उदार साख नीति काम कर रही थी। लोगों का जिंदगी के सामान्य हो जाने में विश्वास लौटा तो ये सभी आर्थिक प्रयास सफल होने लगे।

इस बीच सरकार की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की घोषणा और वित्त मंत्री द्वारा कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता निवेशकों में उत्साह भर रही थी। तभी तो शेयर मार्केटों में जिंदगी की उछाल और विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद में पिछली गिरावट को पूरा कर आगे बढ़ जाने की ललक दिखायी देने लगी। नये बरस की शुरुआत में मिले आंकड़े साहस बढ़ा रहे थे कि कृषि और विनिर्माण क्षेत्र ने तरक्की की है, इसी तेवर के कारण देश 9.2 प्रतिशत विकास दर पर पहुंच जायेगा, जो कि भारत के लिए स्वतः स्फूर्त दर है।

लेकिन नए बरस की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर के आगमन का यह अप्रिय कुठाराघात! ओमीक्रोन वायरस के संक्रमण के समाचार कर्नाटक से मिले थे। देखते ही देखते ये समाचार देश के हर राज्य से आने लगे। वहीं इसके साथ दूसरी लहर का डेल्टा प्लस भी तेज होकर अपना

संक्रामक प्रभाव दिखाने लगा। तेजी इतनी कि अगर पहली लहर में एक लाख लोगों के संक्रमण का आंकड़ा 149 दिन में पहुंचा था, दूसरी लहर में पचास दिन में और अब मात्र ग्यारह दिन में दोनों वायरसों से संक्रमण का आंकड़ा एक लाख से ऊपर हो गया। इसकी गिरफ्त में केवल महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ही नहीं आए, बल्कि पंजाब और हरियाणा भी इसकी गंभीरता झेलने लगे। पंजाब में तो पांच दिनों में संक्रमण ने तीन गुना हो जाने की तेजी दिखाई।

देश के लिए इस महामारी जिसे दोनों वायरसों के संक्रमण के कारण डेल्माक्रोन कहा जा रहा है, की पुनः अग्निपरीक्षा शुरू हो गई। लेकिन इस अग्निपरीक्षा से न केवल प्रशासन, बल्कि किसानों, निवेशकों और कामगारों को भी सामना करके सफल होकर निकलना है। जो गलतियां पिछले वर्ष के शुरू के महीने में दूसरी लहर में झेलीं, वह इस बार न हों।

यह लहर हर स्तर पर अधिक तैयारी और अधिक साहस की अपेक्षा कर रही है। पहले तो दोनों महामारियों के प्रकोप से उबरकर संवरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना है। पूर्ण और अपूर्ण लॉकडाउन चलती अर्थव्यवस्था को रोक अवरोध और क्षरण का माहौल पैदा कर देते हैं। इसलिए इस बार सम्पूर्ण के आदेशों के स्थान पर परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय बंदिशों के आदेश दिए जाए और स्थिति सुधरते ही उन्हें हटा दिया जाए।

कटु सत्यों की अवहेलना ही हमें बार-बार इस मझधार में ले आती है। क्या कारण था कि, जबकि पश्चिमी देशों में कोरोना की तीसरी लहर रंग दिखाने लगी थी, हमने अपने देश में इसके संभावित आगमन की उपेक्षा कर के टीकाकरण की गति को धीमा कर दिया। लोगों ने अपने व्यावहारिक जीवन में सामाजिक अंतर न रखने और चेहरों पर मास्क न पहनने का जीवन फिर से जीना शुरू कर दिया। रिपोर्ट तो यह कहती है कि, भारत ने अपने द्वारा निर्मित टीकों का एक हिस्सा जरूरतमंद देशों को देना शुरू कर दिया और टीका लगाने वाली सिरिंजों का उत्पादन भी कम हुआ।

अब इन हिमालय जैसी भूलों के सुधार के लिए प्रचार अभियान चलाया जा रहा है लेकिन प्रश्न है कि, देश ने कोरोना लहरों के पुनः आगमन की अनिवार्य संभावना को अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया? उसके अनुरूप अपनी जीवनशैली को क्यों नहीं बदला? ये टीके कोरोना निरोधी हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले। सही है कि, भारत द्वारा बनाये गये को-वैक्सीन टीके सफल रहे हैं। लेकिन शोध का यह कारवां द्रुत गति से चलता हुआ अभी तक कोरोना के सटीक उपचार तक क्यों नहीं पहुंचा? पश्चिम के चिकित्सा विज्ञानियों ने इसके उपचार के लिए एंटी वायरल दवा विकसित की है। इसके दाम घटाकर, सहज उपलब्ध बनाकर अभी तक अपने देश की हर दवा मंडी तक पहुंच जाना चाहिये था। ऐसा क्यों नहीं हुआ?

चिकित्सा ढांचे का विकास हो। साथ ही दवा मंडियों में पैदा हो जाने वाली जमाखोरी और कालाबाजारी का निराकरण जरूरी है, यह कमी पिछली लहर के समय इस देश के लोगों ने झेली। सामान्य जिंदगी को ओर लौटने के नाम पर हमेशा प्रशासनिक व्यवस्था और आम आदमी द्वारा पुराने ढर्रे की ओर लौटना क्यों होता है? सामान्य जिंदगी के नाम पर इस अस्वस्थ ललक ने ही आज पूरे देश को महामारी की विकट लहर के तीसरे दौर के समक्ष खड़ा कर दिया है। स्थिति के अनुरूप जिंदगी जीने के ढंग में स्थायी परिवर्तन अर्थात? शारीरिक अंतर रखने और मास्क पहनने का अनुशासन ही इस देश के लोगों को अपनी हाराकिरी से बचा सकता है। इसी प्रकार, मुसीबत पड़ने पर ही प्रशासन सचेत हो, के स्थान पर अगर सदैव सचेत और ठोस निर्णय लेने की सरकारी तत्परता उपज सके, तो सम्भवतः इन क्रमशः आ धमकने वाले मौत के हरकारों से देश को छुटकारा मिल जाए।

गूंज की पहल के बाद अवैध हथियार को लेकर पुलिस आई हरकत में

8 पिस्टल, 11 कारतूस के साथ 11 युवक गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

विगत दिनों शहर के बीच लोकेंद्र टॉकीज के बाहर हुई गोली चलाने की वारदात के बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को मय पिस्तौल गिरफ्तार किया था। मामले में माही की गूंज ने पुलिस प्रशासन का इस और ध्यान आकर्षित किया था कि, लगातार रतलाम जिले में बढ़ रहे अपराधो में अवैध हथियारों का जमकर प्रयोग हो रहा है और पुलिस कई वारदातों को ट्रेस कर अवैध हथियार जप्त भी करती हैं, लेकिन इन अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाली गैंग की ओर पुलिस आज तक नही पहुँच सकी हैं। गूंज द्वारा उठाए गए अवैध हथियार के मुद्दे पर रतलाम पुलिस हरकत में आई और अवैध हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाई, जसमे रतलाम पुलिस को सफलता मिली है।

पुलिस ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मुखबीर से मिली सूचना पर 8 पिस्टल, 11 कारतूस के साथ 11 युवकों को अलग-अलग स्थान से पकड़ा है।

पुलिस के अनुसार 16 जनवरी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि, करमदी के नमकीन कलस्टर क्षेत्र में सुनील नाम का एक युवक पीले रंग की जैकेट पहन खड़ा है व उसके पास पिस्टल है। पुलिस ने इसके बाद सूचना को अपने स्तर पर छानबीन करते हुए सही पाया। इसके बाद दल-बल के साथ पुलिस पहुंची व सुनील की तलाशी ली तो ग्राम झिंझोटा थाना राजोद जिला धार के सुनील (21) के पास एक पिस्टल व एक कारतूस पाया गया। इसके बाद गिरफ्तार करते हुए और जानकारी ली गई।

पिस्टल व कारतूस की बिक्री 20 से 25 हजार रुपये में

सुनील ने पूछताछ में बताया, उसने पिस्टल व कारतूस अविनाश उर्फ अर्जुन निवासी सिंघाना जिला धार थाना मनावर क्षेत्र से ली है। इस दौरान बताया गया कि, कुल 7 पिस्टल खरीदी गई, इसमे से सुरेश उर्फ सूर्या पाटीदार बिरमावाल निवासी जिला रतलाम को 2 पिस्टल व 3 राउंड कारतूस, लक्की कांठा निवासी रानीखेड़ी राजोद जिला धार को 2 पिस्टल व 2 कारतूस, समीर मेहबूब निवासी राजोद जिला धार को एक पिस्टल व एक कारतूस, अर्पित उर्फ गोलू हंस निवासी रतलाम को एक पिस्टल व 2 राउंड कारतूस की बिक्री 20 से 25 हजार रुपये में की है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दल बनाया व अलग-अलग स्थान पर दबिश दी। इसके बाद सूर्या पाटीदार से एक पिस्टल व कारतूस जब्त किया, जबकि एक अन्य पिस्टल व कारतूस उसने अपने मित्र अर्पित उर्फविक्की निवासी संदला को बिक्री करना बताया। जब अर्पित को पकड़ा तो उसने ली गई पिस्टल को सुभाष पाटीदार निवासी संदना को बिक्री करना बताया। सुभाष ने हथियार की बिक्री एक अन्य युवक किशन निवासी रतलाम को बिक्री करना बताया। पुलिस का कहना है कि, अवैध हथियार सप्लाई करने वालो के विरुद्ध मुहिम जारी रहेगी।

डकैती की योजना बनाते आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, मंदसौर।

भानपुरा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के वाहन और हथियार भी जब्त किए गए हैं। डकैती में शामिल दो आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भानपुरा थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी ने बताया कि, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, कुछ लोग पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने भानपुरा के बड़ा महादेव रोड इंद्रगढ़ के निकट सुनसान इलाके में दबिश दी। जहां से राहुल पिता बसंतीलाल बांछड़ा (22), सुनील, पिता फूलचंद्र बांसवाड़ा (22) और कालू, पिता मुकुंद बाछड़ा (22) को मौके से गिरफ्तार किया है। जबकि इनके दो साथी राजाराम पिता रामेश्वर बाछड़ा निवासी नावली गुलाब नगर और राजस्थान चित्तौड़गढ़ के रेनखेड़ा निवासी पप्पू गुर्जर पिता मदन गुर्जर मौके से फरार हो गए।

घटना स्थल से देशी कट्टा बरामद

पुलिस ने बताया कि, आरोपियों के कब्जे से उज्जैन जिले से चोरी हुई एक पिकअप और चोरी की 6 बाइक के साथ एक देशी कट्टा, चाकू, लाठियां और मिर्च पाउडर जब्त किया है। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में कबूल किया है कि, आरोपी भानपुरा के निकट एक पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश रच रहे थे। पुलिस को आशंका है कि, आरोपियों ने और भी वारदातों को अंजाम दिया होगा। पुलिस चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी।

चोर मस्त पुलिस पस्त, एक रात में चार जगह चोरी को दिया अंजाम

माही की गूंज, मन्दसौर।

दलौदा थाना क्षेत्र में चोरों की लगातार आमद बनी हुई है। पुलिस की न तो सख्ती दिख रही है और न ही रात्रि गश्त हो रही है। महू-नीमच राजमार्ग के ग्राम फ्तेहगढ़ से सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात में चाचा-भतीजे की दो मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोर मोटरसाइकल ले गए और अपने जूते वहीं छोड़ गएं। चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए है पर पुलिस की पकड़ से दूर है। इसी रात में फ्तेहगढ़-दलौदा के बीच से बिजली कंपनी के दो ट्रांसफार्मर से आइल भी चुरा ले गए। दलौदा थाना प्रभारी संजीवसिंह परिहार को मंगलवार शाम तक यह पता नहीं था कि, फ्तेहगढ़ में क्या चोरी हुआ हैं।

ग्राम के बद्रीलाल प्रजापत की बाइक एमपी 09 एमटी 8687 व उनके अंकल सुंदरलाल प्रजापत की बाइक एमपी 43 बीबी 4603 चोरी हो गई। मंगलवार को फरियादी आवेदन लेकर दलौदा थाने पहुंचे। फरियादी ने आवेदन में बताया कि, सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब तीन बजे कुछ आवाजे आने पर हमारी नींद खुली। बाहर आए तो मेरी मोटरसाइकल गायब थी मेरे अंकल के यहां देखा तो उनकी भी मोटरसाइकल गायब थी। तब हमे अंदेशा हुआ कि, दोनों बाइक चोरी हो गई है। इस घटना में घर के बाहर जूते पड़े मिले जो की चोरों ने बाहर खोले थे।

दूसरी ओर अन्य मामले में फ्तेहगढ़-दलौदा के बीच में दो ट्रांसफार्मर जो चंदन फैक्ट्री वाला व देवीलाल लोहार के नाम से हैं उनका भी आइल चुरा ले गए। यह ट्रांसफार्मर सांईराज स्टील व वीनस एलाइज फैक्ट्री के आसपास लगे हैं। उनकी लाइन काटकर आइल चोरी कर लिया गया। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी दलौदा के प्रभारी ने भी दलौदा थाने पर आवेदन दिया है। इसमें बताया गया कि, लाइट बंद होने पर ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि दोनों ट्रांसफार्मर से आइल चोरी हो गया है। दलौदा से पहुंचे लाइनमैन ने दोनों ट्रांसफार्मर का निरीक्षण किया तो देखा कि, ट्रांसफार्मर के डीओ कटे हुए है। 11 केवी लाइन का इंसुलेटर खुला हुआ है, आइल ट्रांसफार्मर के आसपास फैला हुआ हैं। विद्युत कंपनी ने चोरी गए आइल की अनुमानित कीमत 7 हजार रुपए बताई है। ग्रामीणों में लगातार बढ़ रही चोरियों से काफी रोष है।

चोरी की घटनाएं पहले दलौदा में हुई थी, वहां भी चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे पर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर ही है। इसके अलावा दो घटनाएं और हो गई है। दलौदा थाने में लगातार चोरियां होने के बाद अब लोग खुद ही गश्त कर रहे हैं। दलौदा की प्रत्येक कालोनी में रहवासी ही गश्त कर रहे हैं। यह भी दलौदा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

चोरी की घटना के बाद जब थाना प्रभारी संजीवसिंह परिहार से चर्चा की तो उनका कहना था कि, फ्तेहगढ़ में चोरी हुई है वहां क्या गया है यह पता नहीं हैं। हम क्षेत्र में लगातार गश्ती करा रहे हैं। धमनार, धुंधड़का, दलौदा सहित सात-आठ जगह गश्त कर रहे हैं, अब फ्तेहगढ़ में भी शुरू करा देंगे। जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे।

2022 में पूरा करना होगा पीएम आवास योजना का कार्य

अधिकारियों की लेटलतीफी के चलते अटके 600 से ज्यादा प्रकरण

माही की गूंज, मंदसौर।

एक तरफ तो राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित हितग्राहियों को लाभ मिले इसके लिए तेजी से प्रयास कर रही है। तो दूसरी अधिकारियों के द्वारा पात्र हितग्राहियों को लाभ समय पर मिले इसके लिए काम नहीं कर रहे है। जिसके चलते कई हितग्राही तो एक वर्ष से अपने सपनों का मकान बनाने का इंतजार कर रहे है। दरअसल, नगर निकायों के द्वारा पात्र हितग्राहियों की सूची भोपाल भेजी गई है। लेकिन वहां जिले के सैंकड़ों प्रकरण अटके पड़े है। जिसके चलते मकान बनाने में देरी हो रही है। इसके साथ ही मंहगाई का सामना भी हितग्राहियों को करना पड़ेगा।

2022 में करना है पूरा टारगेट

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्तमान वर्ष में ही मिलेगा। इसके लिए बकायदा नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है। जिसके तहत सभी नगरीय निकायों के पात्र हितग्राहियों को लाभ देने और उनसे आवेदन मंगवाने के लिए लिखा गया है। 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतिम वर्ष है, इस आदेश के बाद जिले में नगर पालिका से नगर निकायों के द्वारा नगरों में मुनादी करवाई गई है तो विज्ञप्ति प्रकाशित कर सूचना भी दी जा रही है।

तीन सौ से अधिक प्रकरण लंबित

जिले में कई ऐसे नगर निकाय है जिनके द्वारा भोपाल में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के लिए प्रकरण भेजे गए है। करीब तीन सौ से अधिक प्रकरण ऐसे है जो वहां पर अटके हुए है। यह प्रकरण पांच या दस दिन नहीं बल्कि किसी निकाय को एक तो किसी निकाय को दो माह हो गए है। अब तक वहां से स्वीकृति की सूची जारी नहीं की गई है। जिसके चलते हितग्राहियों को इंतजार करना पड़ रहा है।

यूं हो रहा मकान बनाना मंहगा

जानकारी के अनुसार गरोठ में 107, शामगढ़ में 300 तो सीतामऊ के 100 प्रकरण भोपाल में लंबित है। हाल ही में ही मंदसौर नगर पालिक के करीब 600 प्रकरण स्वीकृत हुए है। इन तीनों निकायों में जिन हितग्राहियों के प्रकरण भोपाल में स्वीकृति के लिए अटके है। किसी ने एक साल तो किसी ने छह माह पहले आवेदन किया था। जब ईट, रेत, सीमेंट, मजदूरी सहित अन्य के भाव कम थे। लेकिन आज की स्थिति में घर बनाना करीब 24 से 34 प्रतिशत महंगा हो गया है। जिसके चलते आर्थिक मार भी हितग्राही पर पड़ेगी।

मिलावटखोरों के विरुद्ध क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में मिलावटखोरी की लगातार शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने आयोजित बैठक में खाद्यान्न अधिकारी से पूछा कि, मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, छोटी-मोटी इस हंसी-मजाक वाली सेंपलिंग से कोई लाभ नहीं। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जमरा से सख्त नाराज रहे।

इस दौरान अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने कहा कि, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जिले में जो कार्रवाई की जा रही है वह प्रभावी नहीं है। इनके द्वारा छोटी दुकानों के प्रकरण बनाए जाते हैं, बड़े दुकानदारों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाता है। प्रकरण ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं लगता है। अपर कलेक्टर ने बताया कि, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटी दुकानों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, सैंपल लिए जाते हैं, शहरी क्षेत्र में इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने कहा कि, आगे से मिलावट के संबंध में कोई शिकायत आएगी तो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर जमरा निलंबित कर दिए जाएंगे। कलेक्टर ने जमरा को विगत दो माह में क्या काम किया गया है, नोटशीट पर लाकर बताने का भी निर्देश दिया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, कृतिका भीमावद तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि, राशन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करें। सभी एसडीएम से कहा कि, राशन दुकानों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की तय समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर प्रशासनिक मशीनरी को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं और सभी विभागों के अधिकारियों को जनता से जुड़े मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं और कलेक्टर खुद भी आए दिन मैदान में उतर कर जनता के बीच जा रहे हैं।

गांधी सागर बांध को लेकर कैग की चौकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

दो राज्यों के 7 जिलों की आबादी खतरे में

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर स्थित गांधी सागर बांध को लेकर कैग की रिपोर्ट के बाद मध्यप्रदेश डैम सेफ्टी डायरेक्टर व बोधी विंग का पांच सदस्यीय जॉच दल गांधीसागर पहुँचा, जहाँ जांच दल द्वारा बांध से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की गहनता से निरीक्षण किया गया। जिसमें छोटे-बड़े कार्य मिलाकर 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। यह राशि केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से मिलेगी। इन कार्यों को पूरा होने में 2 से 3 वर्ष लगेंगे।

5 जनवरी को कैग की तरफ से जारी रिपोर्ट में गांधीसागर बांध को सुरक्षा की दृष्टी से बेहद संवेदनशील माना गया था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि, बांध की डाउन स्ट्रीम में स्पिलवे के ठीक नीचे में गहरे गड्ढे हो गए हैं और स्पिलवे भी डैमेज हो गया है। यदि बांध की जल्द से जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो निकट भविष्य में इसके डाउन स्ट्रीम में रहने वाली राजस्थान और मध्यप्रदेश के 7 जिलों की 30 से 40 लाख की आबादी को खतरा है।

वही 2019 जैसी बाढ़ का पूर्वानुमान 13 रिपोर्टिंग स्टेशनों पर बारिश के आंकड़ों से लगाया जाता था। कुशल कर्मचारियों के अभाव में डिस्चार्ज साइट का डेटा ठीक से नहीं रखा जाता था, इस कारण बारिश और बहाव के बीच कोई सामंजस्य विकसित नहीं किया जा सका। इसलिए बांध पर तुरंत एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर मौसम विभाग के डेटा सेंटर से जोड़कर बाढ़, बारिश और चक्रवात के पूर्वानुमान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की सिफारिश रिपोर्ट में की गई थी।

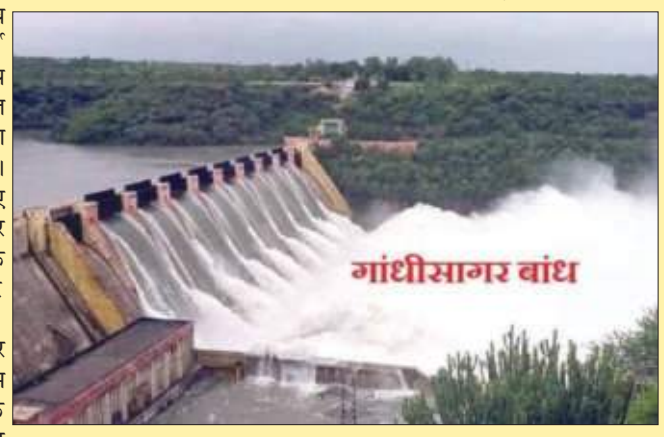

उक्त रिपोर्ट जब मध्यप्रदेश बांध सुरक्षा डायरेक्टर व बोधी विंग के पास पहुंची तो उनकी तरफसे 5 सदस्यो का दल 11 जनवरी को गांधीसागर पहुंचा, दल के साथ गांधीसगर बांध कार्यपालन यंत्री एचके मालवीय व एसडीओ के साथ जॉच में डीएल द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमे पाया गया कि, 2019 में अधिक मात्रा में जल भराव व प्राकृतिक आपदा से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है।

गांधीसागर बांध कार्यपालन यंत्री एचके मालवीय ने बताया कि, अभी 10 जनवरी को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बांध का निरीक्षण किया था। इसमें कई सारे कार्य मिलाकर 100 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई है। मार्च तक डीपीआर को पास कराकर टेंडर करा लेंगे। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मानसून के दौरान बांध में जलभराव का स्तर भी तय कर दिया गया है। हालांकि बाँध पूरी तरह सुरक्षित है उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।

सुरक्षा की दृष्टि से बांध में तकनीकी का प्रयोग जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, बेठिमेट्रिक सर्वे, इस्काड़ा सर्वे व अन्य टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर बांध को जल भराव व सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं बांध की सीमा में पठार होने से चट्टानों का घिरना रोकने के लिए शॉर्ट क्रीटिंग कर मार्ग व बांध को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि, अत्यधिक जल भराव को लेकर डीएसआईपी विभाग द्वारा 2006 में टनल पाईप लाईन टेक्नोलोजी का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित हुआ था। जिसमे एक सुरंग के निर्माण की सिफारिश की गई थी, जिसमें जलाशय के बायी ओर 500 मीटर ऊपरी धारा से पानी को मोड़कर बांध के नीचे की ओर 500 मीटर दूर छोड़े जाने को कहा था। लेकिन इस प्रयोग से अन्य राज्यो में स्तिथ बांध क्षतिग्रस्त हो सकते थे, इसलिए इस प्रस्ताव को बंद कर दिया गया है।

न्यूज ब्रीफ

दादा-पोती का श्रिता शर्मसार करने वाले आरोपी को दी 3 वर्ष की सजा

माही की गूंज, बड़वानी।

तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा ने अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड करने के आरोप मे आरोपी दादा को धारा 354, 354(ख) भादवि 7/8 पाक्सो एक्ट मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 600 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत बड़वानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि, पीडिता के पिता की मृत्यु होने के बाद पीडिता की माता ने दुसरा विवाह कर लिया था। इसलिए पीडिता और उसका भाई उनके दादा के साथ रहते थे। घटना 4 अप्रैल 2020 की है, पीडिता और उसका दादा अलग-अलग सो रहे थे ओर पीडिता का भाई का उसके पडोस में सो रहा था। तभी रात्री में पीडिता के दादाजी ने पीडिता के साथ अश्लील हरकत की व उसके वस्त्रहरण की कोशिश की। तब पीडिता रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर उसका भाई पडोस से आ गया। फिर पीडिता ने घटना के बारे में अपने भाई को बताया और सुबह घटना की जानकारी अपनी बुआ को दी। परिवार वालो को साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराकर, प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हाई व हायर सेकेन्ड्री स्कूल की प्री-बोर्ड परीक्षा की सारणी जारी

माही की गूंज, बड़वानी ।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा हाई व हायर सेकेन्ड्री की प्री-बोर्ड की परीक्षा की समय-सारणी जारी कर दी है। कक्षा 10वीं प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 28 जनवरी तक और कक्षा 12 वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा 20 से 31 जनवरी तक टेक होम के रूप में संचालित की जाएगी। संचालक लोक शिक्षण केके द्विवेदी ने बताया कि, प्री-बोर्ड परीक्षा संचालन के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों के प्राचार्य को विस्तृत दिशा-निर्देश कोविड 19 के तहत कार्य करने हेतु जारी कर दिए गए हैं।

एसपी ने पांच आरोपियों पर 13 हजार का ईनाम किया घोषित

माही की गूंज, खरगोन।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने दो प्रकरणों के पॉच आरोपियों पर 13 हजार रूपय को ईनाम देने की उद्घोषणा की है। आरोपियों में जिसान पिता निजामुद्दीन मंसुरी निवासी घोडेसावली सेंधवा, लच्छु ऊर्फ लक्ष्मण पिता सोभाराम (50) निवासी मोतीबाग सेंधवा, तोसिफऊर्फसोबी पिता मुस्तका तथा मुजक्कीर पिता जाकीर (27) निवासी मारू मोहल्ला अंजड जिला बड़वानी पर 2-2 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। इन आरोपियों का थाना भीकनगांव में अपराध क्रमांक 671/2021 की धारा 406, 407, 435, 109, 420, 34, 120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी ने इन आरोपियों को पकड़ने या बन्दी बनाने में पुलिस का सहयोग करने वाले को घोषित ईनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

वहीं एक अन्य प्रकरण के आरोपी आकाल पिता मनोहरसिंह सिकलीगर निवासी नवलपुरा धुलकोट का थाना भगवानपुरा में अपराध क्रमांक 349/2021 की धारा 25ए (1) 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। आकाल को पकड़ने या बन्दी बनाने में पुलिस का सहयोग करने वाले को पुलिस अधीक्षक श्री चौधरी द्वारा 5 हजार रूपये का ईनाम दिया जाएगा।

आश्वासन अभियानः संचालित किए जनजागृति रथ, करेंगे टीबी का सर्वे

माही की गूंज, बड़वानी।

भारत में 100 दिन 100 जिलों में टीबी एवं कोविड के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने हेतु संचालित अभियान ''आश्वासन'' का शुभांरभ बुधवार को जिले में भी किया गया। इसके तहत कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा ने पिरामल स्वास्थ्य द्वारा जिले के सातों विकासखण्डो में घर-घर जाकर टीबी का सर्वे करने एवं टीबी के प्रारंभिक लक्षण वाले लोगो की पहचान करने हेतु संचालित जनजागृति रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि, पिरामल स्वास्थ्य के सहयोग से हम भी बड़वानी जिले को टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे। इस वाहन के माध्यम से जहा घर-घर होने वाले सर्वे को और प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। वहीं प्रारंभिक टीबी के लक्षण युक्त लोगो के खखार का कलेक्शन कर उसका परीक्षण समय पर करवाया जा सकेगा।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे एवं पिरामल के पदाधिकारी असलम शेख ने बताया कि, पिरामल स्वास्थ्य द्वारा बड़वानी जिले के 7 विकासखंडों में प्रचार-प्रसार वाहनों के माध्यम से टीबी के संभावित मरीजों की खोज की जायेगी। लक्षणों के आधार पर बलगम की जांच करवाई जायेगी, यदि इसमें रोग की पुष्टि हो जाती है तो संबंधित को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे निःशुल्क टीबी के इलाज की सुविधा भी प्रदान करवाई जायेगी। जिससे इस टीबी जैसे संक्रामक रोग को फैलने से रोका जा सके।

इस दौरान बताया गया कि, सामुदायिक सहभागिता के पहलू को दृष्टिगत रखते हुए अभियान के दौरान ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रभावशाली लोगों एवं परंपरागत वैद्यों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। जिससे गांव को टीबी मुक्त किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि, यूएसएड द्वारा वित्तपोषित परियोजना को पिरामल स्वास्थ्य के ''अनामय कार्यक्रम'' के माध्यम से जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला क्षय यूनिट की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

कलेक्टरेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे, जिला क्षय अधिकारी डॉ. प्रमोद गुप्ता, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मी माहौर, पिरामल स्वास्थ्य से असलम शेख, रामकृष्ण यादव, हितेश पाण्डेय के साथ पिरामल स्वास्थ्य के फील्ड स्तरीय कम्युनिटी मोबीलाईजर एवं पैरामेडिकल स्टॉफतथा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे।

विकासखण्डो में प्रारंभ हुआ अभियान

पिरामल स्वास्थ्य के सहयोग से संचालित इन वाहनों के विकासखण्ड मुख्यालय पहुंचने पर संबंधित एसडीएम, विकासखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों, चिकित्सको ने अविलम्ब इन रथों को प्रशिक्षित टीमो के साथ ग्रामों में जनजागृति हेतु रवाना किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों उपस्थित लोगो को इस अभियान की उपयोगिता से भी अवगत कराया।

प्रभारी मंत्री हरदीपसिंह डंग ने की वैक्सीनेशन एवं कोरोना पाजिटिव केसो के ईलाज की समुचित व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले के प्रभारी मंत्री हरदीपसिंह डंग ने जिले में पहुंचकर वैक्सीनेशन एवं कोरोना पाजिटिव केसो के ईलाज की समुचित व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर, आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। इस दौरान लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल, कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराजसिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिता सिंगारे, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ. लक्ष्मी माहौर उपस्थित थी

कलेक्टरेट सभागृह बड़वानी में आयोजित बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री हरदीपसिंह डंग ने जिले में कोरोना की रोकथाम हेतु चल रहे वैक्सीनेशन कार्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि, कोरोना पाजिटिव प्रकरणों में होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की नियमित काउंसलिंग एवं उपचार की जानकारी लेने की व्यवस्था सतत् बनाई रखी जाये। इस दौरान यदि किसी पाजिटिव व्यक्ति के घर में समुचित प्रबंधन नही हो रहा है तो उसे अविलंब कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर चिकित्सकों की देखरेख में रखा जाये। इसी प्रकार उन्होने जिले के विभिन्न स्थानों पर बनाये गये कोविड केयर सेंटर की समीक्षा करते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे सहयोग एवं व्यवस्था की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।

समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि, विभिन्न स्थानों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में स्थापित आक्सीजन निर्माण संयंत्र का नियमित निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता रहे। जिससे आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग तत्काल किया जा सके। साथ ही उन्होने फीवर क्लिनिक की समीक्षा करते हुए इनके माध्यम से एवं आकस्मिक रूप से लोगों के अधिक से अधिक सैम्पल लेकर उसकी जांच कराने की नीति को सतत् बनाये रखने के भी निर्देश दिये। जिससे प्रारंभिक लक्षणों के दौरान ही पाजिटिव केस को ढूंढकर उन्हे आइसोलेट करवाते हुए कोरोना के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री को फीवर क्लिनिक, आक्सीजन प्लांट, सीटी स्कैन मशीन, जिला कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर, संजीवनी क्लिनिक, जिले में पाजिटिव आये केसों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था एवं उपचार की सुविधा, विदेशों से आये व्यक्तियों को आइसोलेटेड करवाने की व्यवस्था के बारे में विस्तार से अवगता कराया।

मोबोलाइजर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने हेतु जनपद सीईओ को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद (झाबुआ)।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम (आरजीएसए) अंतर्गत पैसा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा पेसा मोबिलाईजर का चयन किया गया था। जिसके चयन प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा डब्लयुपी नं. 2825/2021 द्वारा 15 फरवरी 2021 को मोबिलाईजर चयन प्रक्रिया में स्थगन आदेश जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश में सुनवाई करते हुए 17 नवम्बर 2021 को निर्णय लिया जाकर स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया। संचालनालय के पत्र क्रमांक/14904 31 दिसम्बर 2020 अनुसार ग्राम सभा पेसा मोबिलाईजर के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/517/पं.रा./आरजीएसए/2022 भोपाल 12 जनवरी 2022 को संचालनालय ने पुनः भर्ती आदेश जारी किए हैं। आदेश की जानकारी के बाद मोबोलाइजर पद के लिए चयनित और आवेंदन करने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को जनपद कार्यालय पहुच कर सीईओ अमित व्यास को ज्ञापन सौप कर मोबोलाइजर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, सीईओ अमित व्यास ने सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है।

सैनिक कोष में राशि जमा करने का लक्ष्य प्राप्त, राज्यपाल ने सौंपा प्रशस्ति पत्र

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और प्रभावितों को सहयोग करने में लगातार रिकार्ड दर्ज किया है। सैनिक कल्याण विभाग के विंग कमांडर एम नासिर ने टीएल बैठक से पूर्व कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी को राज्यपाल द्वारा जिले को प्राप्त प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री नासिर ने कहा कि, खरगोन जिला, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी की तुलना में ऐसा जिला है जो लगातार वर्षो से फ्लैग डे पर एकत्रित होने वाली राशि का लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। जिले ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस वर्ष 2020-21 में लक्ष्य 7 लाख 47 हजार रुपए से अधिक 8 लाख 41 हजार 210 रुपए धन राशि एकत्रित करने में खरगोन जिले का नाम प्रथम स्थान पर रहा। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र विंग कमांडर एम नासिर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी खंडवा को राज भवन भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया गया।

कलेक्टर कार्यालय खरगोन के सभागृह में समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र सौंपे गए। इस उपलक्ष्य में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खंडवा के विंग कमांडर ने कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा एवं समस्त उपस्थित अधिकारियों की इस पुनीत कार्य के लिए भूरी-भूरी प्रशंसा की तथा खरगोन जिले के समस्त नागरिकों का धन्यवाद भी दिया गया। इस अवसर पर चंद्रभानु सिंह मण्डलोई कार्यालय अधीक्षक उपस्थित थे।

झंडा दिवस के रूप में एकत्रित राशि का उपयोग सेना में शहीद हुए सैनिकों के

बच्चों, विकलांग सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों की विधवाओं उनके बच्चों के कल्याण और उपयोग में ली जाती है। सेना के सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए एकत्रित की जाने वाली इस राशि को लगातार 2 वर्षो से लक्ष्य से अधिक खरगोन जिले में एकत्रित किया गया।

जानलेवा चाइना धागा बेचने वालो के विरुद्ध हो रही कार्रवाई

माही की गूंज, खरगोन।

पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) इन्दौर जोन के राकेश गुप्ता व पुलिस उप. महानिरीक्षक निमाड रेंज तिलकसिंह द्वारा जिले में अवैध रूप से बिक रहे पतंग उड़ाने में उपयोग किए जा रहे जानलेवा चाइना धागे पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जितेन्द्रसिंह पंवार, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) डॉ. नीरज चौरसिया के निर्देशन में जिले के समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए नर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में थाना कोतवाली खरगोन, थाना मेंनगाँव, थाना मंडलेश्वर एवं थाना सनावाद अवैध रूप से बिक रहे पतंग उड़ाने मे उपयोग किए जा रहे चाइना धागे जप्त कर कार्रवाई की गई है। जिले में पतंग उड़ाने मे उपयोग किए जा रहे जानलेवा सिनथेटिक चाइना धागा बेचने वालों पर पुलिस टीम द्वारा पृथक-पृथक

कार्यवाही कर जानलेवा सिनथेटिक चाइना धागे को जप्त किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है।

कोतवाली खरगोन में 35/22 धारा 336 भादवि एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 चायना माजा सिनथेटिक के 2 बण्डल किमती 200 रूपये, मेंनगाँव थाने 17/22 धारा 336 भादवि एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- 5 चायना माजा सिनथेटिक के 2 बण्डल किमत 200 रूपये, सनावद में 26/22 धारा 336 भादवी एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 एक बड़ा बण्डल एवं एक पैकेट में 9 रंग बिरंगे छोटे बण्डल चायना मांजा धागे के कीमत एक हजार 200 रूपये, मंडलेश्वर थाने में 16/22 धारा 336 भादवी एवं मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 बंडल चायना माजा किमत 200 रुपए का जप्त किया है। पुलिस की जनता से अपील पुलिस की जनता से अपील है कि, पतंग उड़ाने के लिए सिनथेटिक चायना माँजे का उपयोग न करे सिनथेटिक चायना माँजे का उपयोग जानलेवा हो सकता है।

कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ श्री पंचमुखी हनुमानजी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव

चार दिवसीय विशेष आयोजन के साथ होगी प्राण प्रतिष्ठा

माही की गूंज, पेटलावद (झाबुआ)।

नगर की माधव कॉलोनी स्थित शंकर मन्दिर परिसर मे 18 तारीख से 22 तारीख तक चलने वाले श्री पंचमुखी हनुमानजी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कलश यात्रा के साथ मंगलवार से प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा कॉलोनी के शंकर मंदिर से शुरू होकर नए बस स्टैंड होते हुए साई मंदिर पँहुची। यहा से वापस माधव कॉलोनी शंकर मंदिर पर पंहुची। यात्रा में महिलाओं ने एक जैसी वेशभूषा पहनी। मंदिर के पंडित व अन्य पंडित भी यात्रा में शामिल हुए। हाथ मे ध्वजा ओर माथे पल कलश लिए भी कई श्रद्धालु शामिल हुए। बुधवार को यज्ञ ओर गुरूवार को नवचंडी यज्ञ होगा। वंही शनिवार को पूर्ण आहुति ओर प्राण प्रतिष्ठा एवं महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा।

शंकर मदिर के पुजारी अशोक रमावत द्वारा बताया गया कि, सारे आयोजन कोरोना गाईडलाईन के अनुसार करवाए जाएंगे। मास्क, सेनेटाईजर ओर सोशल डीस्टेंस का भी पालन करवाया जाएगा। इस आयोजन में दुर दराज से संत पधारेंगे।

गूंज असरः खबर प्रकाशित होने के बाद जागा प्रशासन

नगर में बिना मास्क घूमने वालों पर हो रही चालानी कार्रवाई

माही की गूंज, अलीराजपुर।

माही की गूंज के पिछले अंक में ''लापरवाहीः बिना मास्क के बाजार घूम रहे लोग, सोशल डिस्टनसिंग का भी नही हो रहा पालन'' शीर्षक के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। जिसमे बताया था कि, किस प्रकार नगर में कोरोना को लेकर लापरवाही देखने को मिल रही थी। शहर के बाजार में फिर संक्रमण के प्रति लापरवाही नजर आने लगी थी। लोगों के मुंह से मास्क हट गए थे और शारीरिक दूरी को भुला दिया गया था। इधर प्रशासन की इस ढील का असर बाजार के अलावा, प्रमुख चौराहों पर भी देखने को मिल रहा था। खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया और नगर के प्रमुख चौराहो पर बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही। चालानी कार्रवाई में अलीराजपुर एसडीएम लक्ष्मी गामड़, एसडीओपी श्रद्धा सोनकर, नायब तहसीलदार व नगरपालिका परिषद सहित पुलिस द्वारा रोको-टोको अभियान फिर से चलाया जा रहा है। नगर के प्रमुख चौराहे पर बगैर मास्क वालो पर चालानी कार्रवाई की गई बिना मास्क वालो के चालान काटे गए। बिना मास्क वालो के सख्ती से चालान काट कर समझाइश देकर वाहन चालकों को रवाना किया। एसडीएम ने कहा, यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा क्योकि नगर मे संकमण की संख्या दिन पर दिन बढती जा रही है।

लापरवाहीः बिना मास्क के बाजार मे घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेसिंग का भी नही हो रहा पालन

रोको टोको अभियान के साथ चल रही कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प के आदेश पर जिले में राजस्व एवं पुलिस अमला कोविड दिशा निर्देशो का पालन करने हेतु आमजन को जागरूक कर रहा है। साथ ही मास्क नहीं लगाते हुए लापरवाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिले के विभिन्न नगरीय एवं कस्बाई क्षेत्रों में रोको-टोको अभियान के तहत मैदानी अमला मास्क नहीं लगाने वालों को रोक-टोक करते हुए कोरोना से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। जोबट में एसडीएम देवकीनंदन सिंह, अलीराजपुर में एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, सोंडवा में एसडीएम सुश्री प्रियांशी भंवर, चन्द्रशेखर आजाद नगर में एसडीएम सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में मैदानी अमला नगरीय एवं ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में ग्रामीणों को कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे है। निर्देशो का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मैदानी अमला दुकानदारों को सोशल डिस्टेन्सींग का पालन दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं टीकाकरण की दोनों डोज लगाने के लिए भी आमजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बंपर पैदावार के कारण बागवानी कर रहे कृषकों को हुआ लाभ

आमजन को मिल रही ताजी विटामिन युक्त सब्जियां

माही की गूंज, आम्बुआ।

इस वर्ष बारिश कम होने तथा जलाशयों में पर्याप्त जल नहीं होने के कारण ग्रामीणों का रुझान नगद फसल की ओर होने से क्षेत्र में कम पानी से पैदा होने वाली फसलों को पैदा कर तत्काल प्राप्त किया जा रहा है। आम हो या खास सभी को ये ताजी विटामिनों से युक्त बाजार में उत्पादन मिल रहा है।

हम बात कर रहे हैं इस वर्ष अल्प वर्षा के कारण क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बनने की। कम वर्षा के कारण नदी नालों तथा तालाबों, बाउडियों में जल संग्रह क्षमता के अनुरूप नहीं होने के कारण कृषकों ने परंपरागत फसलें गेहूं, चना, सरसों का रकबा कम कर उसके स्थान पर खेतों में मौसमी सब्जियां भिंडी, गोभी, टमाटर, मिर्ची, प्याज, धनिया, गाजर, मूली, बालौर(सेम), ग्वारफली आदि अनेक सब्जियां बोई तथा अब वे उन्हें प्रतिदिन तथा साप्ताहिक हाट बाजारों में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें नगद आय मिल रही है। जबकि अन्य फसलों के तैयार होने तथा बिक्री के बाद भी समय पर भुगतान नहीं मिलता है। मगर सब्जियों की बिक्री पर तत्काल नगद रकम हाथ में आने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति हो जाती है। सब्जी की फसलों में अन्य फसलों से कम पानी देना होता है तथा मेहनत एवं खाद आदि भी कम लगती है वही यह बाजार में प्रतिदिन तत्काल बिक जाती है। ग्रामीण कृषकों के साथ-साथ लोगों को ताजी विटामिन युक्त सब्जियां उचित भाव में मिल जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यही सब्जियां ऊंचे भाव में मिलती है। इस कारण कई नौकरी पैशा लोग ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां, फ्ल आदि खरीद कर ले जाते हैं। स्मरण रहे कि, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली सब्जियां केमिकल तथा रासायनिक खाद पैदा नहीं कर गोबर तथा कम्पोष्ट खाद से पैदा की जाती है जो कि स्वाद में अच्छी होकर सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। आम्बुआ में प्रतिदिन तथा साप्ताहिक हाट बाजार में स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां मिल रही है।

ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं- विधायक पटेल

माही की गूंज, अलीराजपुर।

विधानसभा क्षेत्र अलीराजपुर की हर ग्राम पंचायत में के सभी फलियों में सड़क, बिजली और पेयजल सहित सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मै प्रतिबद्ध हूं और हमेशा रहूंगा। हर गांव और हर फलिये में पेयजल और बिजली की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। जिन गांवों में पेयजल के लिए टैंकर उपलब्ध नहीं है उन गांवों में आगामी समय में पेयजल टैंकर दिया जाएगा। उक्त वक्तव्यं अलीराजपुर विधायक मुकेश पटेल ने बुधवार को बोरखड स्थित विधायक कार्यालय पर विधायक निधि से 19 लाख रूपये की लागत से 12 पेयजल टैंकर 12 ग्राम पंचायतो के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को सौंपते समय कहे।

इन ग्राम पंचायतों को दिए पेयजल टैंकर

विधायक मुकेश पटेल, प्रभारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, पुष्पराज पटेल, दिलीप पटेल आदि ने ग्राम पंचायत सिलोटा, बोडगांव, छोटी वनखड, किलोडा, उमरी (छिनकी), दुधवी, मधुपल्लवी, माछलिया, मोरासा, बोकडिया, केल (झिंझना) और अकलवा में 19 लाख रूपये लागत के 12 पेयजल टैंकर ग्राम के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को प्रदान किए।

आगामी बजट में जिले के विकास को प्राथमिकता दे सरकार

इस दौरान विधायक पटेल ने कहा, आगामी वित्तीय बजट में प्रदेश सरकार को जिले के विकास कार्यो को प्राथमिकता देना चाहिए। कोविड-19 कोरोना महामारी संक्रमण के कारण जिले में पिछले दो वर्ष से विकास कार्य ठप पड गए है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाजजनों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को प्राथमिकता के साथ विकास कार्य की और ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जिले में कोरोना के चलते आदिवासी किसान और मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, इनके विकास कार्यो के लिए विशेष आर्थिक पैकेज सरकार द्वारा तुरंत घोषित करने की मांग विधायक पटेल ने की। कार्यक्रम में खुर्शीद

दीवान विधायक प्रतिनिधि, पुष्पराज पटेल युवा नेता, राहुल भयडिया, राहुल ठहराव, जिग्नेश सस्तिया छोटी वनखड़, अजहर सिलोटा, उदयसिंह पुवासा, सुपरसिंह किलोड़ा, राधेश्याम मधुपलवी, केशरसिंह माछलिया, प्रकाश मोरसा, दिलीप बोकड़िया, कुवरसिंह झिंझना, हरसिंह भिड़े रायछा डिंडवड, कैलाश चौहान ब्लॉक अध्यक्ष खारकुआ, राजू खरपाई, मालसिंह जवानिया, दौलत बोकड़िया और क्षेत्र की जनता सहित आदि उपस्थित थे।

कोरोना पॉजीटीव व्यक्तियों के घर के बाहर लगाए कोविड सूचना बोर्ड

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए राजस्व, पुलिस नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों का अमला आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने हेतु दिशा निर्देश दे रहे है। एसडीएम अलीराजपुर श्रीमती लक्ष्मी गामड, एसडीओपी अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर एवं मैदानी अमले ने आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए जागरूक करते हुए मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की। कोविड पॉजीटीव व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को सावधानी बरतने सहित बाहर नहीं निकलने की हिदायत देते हुए होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से सुनिचित करने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिला प्रशासन की मदद से हर घर के बाहर कोविड सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है, ताकि कोरोना संदिग्धों को अलग रखा जा सके। इनके संपर्क दायरे को रोका जा सके। कोरोना वायरस को लेकर सरकार लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है, साथ ही जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लोगों से कोरोना नियमों की पालना करने की अपील कर रहा है।

नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन के निर्देश है कि, बिना मास्क पर घूमने पर चालान व अन्य कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलने, मास्क का उपयोग करें, शारीरिक दूरी का भी पालन करें, भीड़ भाड़ वाली स्थानों में न जाए और दूसरों को भी इसका पालन करने को कहें। तभी हम आप सभी जन मानस सुरक्षित रह सकेंगे।

कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष आयोजन में कार्यकर्ताओं की ली कार्यशाला समय पर नहीं पहुंचे नेताजी

माही की गूंज, थांदला (झाबुआ)।

प्रदेश कार्यसमिति द्वारा जिले में जिला कार्य समिति प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ आयोजन में जिले के समस्त भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन आयोजन सम्मेलन के प्रभारी इन्दौर सांसद शंकर लालवानी निर्धारित समय से 3 घंटे देरी 3 बजे तक भी नही पहुचे जिसके चलते मंच संभाल रहे नेता कभी अपने सांसद उर्फनेताजी लालवानी जी के बारे में कहते रहे कि, अभी सांसद जी डाक बंगले में है तो कभी पेटलावद में कार्यशाला को संबोधित करने का हवाला देते रहे, इसी दौरान नेताजी की देरी के कारण कई क्षेत्रिय नेता एक-एक, दो-दो करके कार्यशाला से अपने नेताजी के आने के पूर्व ही रवाना हो गए। 3 बजे बाद इंदौर सांसद शंकर लालवानी आए ओर दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में विशेष रुप से उपस्थित अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंग भाबर व कार्यक्रम के अतिथि का स्वागत मंडल अध्यक्ष समर्थ उपाध्याय, नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर, जिला महामंत्री श्यामा ताहेड एवं जिले के भाजपा पदाधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद लालवानी ने अपने संबोधन में कहा कि, देश में कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष के अंतर्गत हम सभी संगठन पर्व 2021-2022 मनाने जा रहे हैं। इस बार पार्टी ने तय किया है कि, जिले से लेकर समस्त मंडल ग्राम केंद्र, नगर, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ संगठन के सभी कार्यकर्ता इस में सम्मिलित होंगे। बूथ विस्तारक को भी जवाबदारी सौंपी जाएगी। इन्हें भी 10 दिन 10 घंटे कार्य करना होगा, वर्ष 2022 में संगठन के निर्णय के अनुरूप समस्त कार्यकर्ता कार्य करेंगे, संपूर्ण जिले से बूथ लेवल तक भाजपा कार्यकर्ता की तैनाती होगी। जिस कार्यकर्ताओं को जो दायित्व सौंपा गया है वह निष्ठा के साथ उसका निर्वाहन करें। कार्यक्रम में मेघनगर मंडल अध्यक्ष सचिन प्रजापत, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान, पूर्व अध्यक्ष भानु भुरिया, प्रणव परमार, अजय सेठिया के साथ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री श्यामा ताहेड ने किया, आभार थांदला मंडल अध्यक्ष समर्थ उपाध्याय ने माना।

सर्द हवाओं ने ढूढरने पर किया मजबूर, बाहर निकलना हुआ मुश्किल

माही की गूंज, आम्बुआ। विगत दिनों से क्षेत्र में चल रही ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आमजन गर्म कपड़ों मे लिपटे तथा घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं।

आम्बुआ ही नहीं अपितु आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत एक सप्ताह से शीतलहर चल रही है, जिस कारण ठंड अधिक होने से सभी परेशान हो रहे हैं। ठंड के कारण दिन-रात का तापमान गिरता जा रहा है हालांकि दिन में सूर्य की धूप निकल रही है इसके बावजूद ठंड में कमी नहीं आ रही है। सर्द हवाओं ने लोगों को ढुढरने पर मजबूर कर दिया है, गर्म कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद घरों में सिमटना पड़ रहा है। बाजार में सुबह व शाम की चहल-पहल कम हो गई है। ठंड तथा बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण भी लोग बाहर घूमना पसंद न करते हुए घरों में रहने में भलाई समझ रहे हैं। आगामी दिनों में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है।

रोज निकल रहे हैं कोरोना मरीज, प्रशासन नहीं दिखा रहा सख्ती

हाट बाजारों में उमड़ती भीड़ पर कोई नियंत्रण नहीं

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ तथा आस-पास के क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ज्ञात अज्ञात मरीजों की सही संख्या भले ही न मिल रही हो मगर फिर भी यह तो पता लग ही रहा है कि कोरोना पीड़ित बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद न तो लोग संभल रहे हैं और न ही प्रशासन की सख्ती कहीं नजर आ रही है। इस कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

आम्बुआ कस्बे में विगत एक सप्ताह से लगभग 5-6 मरीज मिल चुके हैं जिनका उपचार चल रहा है। इसके बावजूद लोग इस बीमारी के प्रति सचेत नहीं हो रहे है, बाजारों में दिनभर भीड़-भाड़ विशेषकर साप्ताहिक हाट बाजार में भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन या साप्ताहिक हाट बाजार के दिन न तो व्यापारी और न ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। दो पहिया वाहन से लेकर यात्री बसों में सफर करने वाले तथा चालक, परिचालक आदि कई है जो बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। रोको-टोको अभियान का ढिंढोरा तो पीटा जा रहा है मगर रोकने वाले कहीं कोई नजर नहीं आ रहे है। स्कूल बंद जरूर कर दी हैं मगर उसके पूर्व स्कूलों में अधिकांश बच्चे बगैर मास्क के नजर आते रहे। 15 से 18 वर्ष वाले किशोर-किशोरियों को वैक्सीन का प्रथम डोज दिया गया यदि इसके साथ-साथ उनका कोरोना टेस्ट भी होता तो अच्छा रहता, एक बार में दो कार्य हो जाते पर ऐसा कोई निर्देश नहीं होने के कारण स्वास्थ्य विभाग के अमले ने केवल वैक्सीनेशन का कार्य किया। इधर 15 जनवरी से स्कूल बंद हो जाने के कारण शेष बचे हुए किशोर-किशोरीयो का वेक्सीनेशन भी प्रभावित हो रहा है।

ईसाई समुदाय ने खोला मोर्चा, एसडीएम को दिया ज्ञापन

माही की गूंज, थांदला (झाबुआ)।

बुधवार को ईसाई समुदाय ने अनुविभागीय अधिकारी कार्याल पहुंच एसडीएम अनिल भाना को महामहिम राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति, राज्यपाल, राज्य मानव अधिकार आयोग, व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ईसाई समुदाय ने उल्लेख किया कि, बीते कुछ समय से आए दिन सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, वाट्सएप, आदि पर ईसाई समाज व अनुयायियों पर आदिवासी समाज सुधार संघ, हिन्दू युवा जनजाति, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल आदि संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त ईसाईयों एवं ईसाई समाज के धर्मगुरुओं, फादर, पास्टर पर झूठे धर्मान्तरण के आरोप लगाए जा रहे। झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाकर, शारीरिक व मानसिक अत्याचार करने, धमकाने पर करवाई की जाए। ज्ञापन में ईसाई समुदाय ने बताया कि, जिले व आसपास में आए दिन ईसाई समाज व उनके अनुयायियों पर कोई न कोई अप्रिय घटनाए घटित हो रही, जिनमे उन पर प्रलोभन देकर प्रमुख रूप से धर्मान्तरण करने का आरोप लगाया जाता है। कही-कही सामान्य व गंभीर मारपीट कर उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। जब से मध्यप्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू हुआ तब से ऊक्त घटनाए ज्यादा घटित होने लगी है। ऊक्त कानून का ये सभी संगठन गलत लाभ उठाकर ईसाई समाज के विरुद्ध सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाकर ऊक्त कानून के तहत प्रकरण दर्ज करवा रहे है। पुलिस द्वारा भी बिना कोई जांच व अन्वेषण के प्रकरण बनाए जा रहे है जो सर्वथा अनुचित है।

संविधान में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

ज्ञापन में ईसाई समुदाय ने अवगत कराया कि, भारत धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष देश होकर भारत के संविधान अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम सभी की धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण और उसके प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42 वे संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पंथनिरपेक्ष पद को जोड़ा गया है। अर्थात भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, तो फिर ईसाई समाज के साथ विभेद क्यो किया जा रहा है। पुलिस और पूरा प्रशासन भी ऊक्त संगठनों के साथ मिलकर ईसाई धर्म एवं समाज के विरुद्ध कार्रवाई को तत्पर है। ज्ञापन के अंत मे चेतावनी देते हुए बताया कि, ऊक्त संगठनों पर सामान्य प्रशासन और पुलिस द्वारा अंकुश न लगाया जाकर वैधानिक कार्रवाई नही की जाएगी तो आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा व अंतरष्ट्रीय स्तर पर भी ऊक्त घटनाओं को रखा जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही सामान्य प्रशासन एवं पुलिस की होगी। इस अवसर पर जोसेफमाल, पीटर बबेरिया, किशोर खड़िया, विकास रावत, हेमराज मईडा, दिनेश डामोर, उर्मिला डामोर, नीलिमा डाबी, क्लेर अड़ आदि मौजूद थे।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव व्यवस्था में हुआ भारी भ्रष्टाचार

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामने आई जानकारी से हुआ भांडाफोड़, आज तक नहीं हुई कार्रवाई

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा

जब बात किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की हो रही हो तो, दिमाग सरकारी भ्रष्टाचार की और ही जाता है। लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो कोई इसकी उम्मीद नही करता कि, सरकारी अमला चुनाव प्रक्रिया में आने वाली राशि को भी अपनी आय का स्त्रोत बना लेगे। मामला विधान सभा चुनाव 2018 का है, जब राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से विभिन्न मदों की राशि निर्वाचन स्थल पोलिंग बूथों पर खर्च करने के लिए आवंटित की गई थी, जिसमें बड़े स्तर पर लेखन कार्य, परिवहन व्यवस्था, यात्रा भत्ता, राशन का मूल्य, भोजन व्यय, लाइट टेंट, बिजली, पानी आदि के लिए झाबुआ जिले की 973 पोलिंग बूथों पर तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सक्सेना झाबुआ, संबंधित अधिकारी झाबुआ, शाखा प्रभारी प्रकाश सिंगाडिया द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। मामले का खुलासा जब हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवीय ने सूचना अधिकार में इसकी जानकारी निकाली। जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ को आदेश जारी किया गया था कि, संबंधित निर्वाचन 2018 विधानसभा चुनाव के लिए जिले की 973 पोलिंग बूथों पर समस्त व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों को व्यवस्था के लिए आदेश जारी करें। जिला पंचायत झाबुआ के पत्र क्रमांक 2824 दिनांक 16 नवम्बर .2018 को यह आदेश जारी किए गए थे, जिसमें समस्त पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहीत नगर परिषद द्वारा ही अपने व्यय से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से मिलने वाली राशि कई मदों की जिले की 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद को नहीं दी गई। जिले की 377 ग्राम पंचायत और थांदला पेटलावद, मेघनगर जिसकी जानकारी आना बाकी हैं एवं झाबुआ तथा राणापुर के द्वारा ही उनके मद की राशि से ही समस्त बूथों पर खर्च होने वाली राशि का खर्च किया गया।

973 पोलिंग बूथों के लिए 24 लाख से अधिक राशि का हुवा था आवंटन

झाबुआ जिले की विधानसभा 2018 के लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से राशन, भोजन व्यवस्था करने के लिए जिले की 973 पोलिंग बूथों पर लगभग 24 लाख 32 हजार 500 रुपये प्रत्येक बूथ पर 2500 की लागत से देने थे, लेकिन पोलिंग बूथों पर 18 लाख 86 हजार 609 रुपये का फर्जी व्यय निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा बता दिया गया। जबकि महोदय समस्त बूथों को यह राशि जारी की गई थी, लेकिन बचत राशि 5 लाख 85 हजार 891 रुपये बता दि गई। जब कि जिले की 377 ग्राम पंचायतों सहित 5 नगर परिषदों के द्वारा ही 973 पोलिंग बूथों पर खुद के मद से राशि खर्च की गई। जिले की 973 पोलिंग बूथों पर प्रचार-प्रसार, रंगाई-पुताई, लेखन कार्य, टेंट, बिजली, पानी आदि कई मदों की राशि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से जिला निर्वाचन शाखा झाबुआ को प्राप्त हुई थी। किंतु 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद द्वारा उनके मद से ही खर्च किए गए निर्वाचन शाखा झाबुआ से ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों को कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेजों का आधार पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है।

जांच के नाम पर गुमराह कर रहा है प्रशासन

निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी और राशि खर्च करने वाली एजेंसी, ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषद से मिली जानकारी से पूरा मामला पानी की तरह साफहो गया कि, तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के लिए खर्च की गई राशि की हेरा-फेरी की है, जिसकी प्रमाणित शिकायत भी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा की गई, जिसको जांच के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता दिलीप मालवीय ने पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर करने की मांग की है।

रिश्वत मांगना एएसआई को पड़ा भारी, लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज

चौकी प्रभारी ने कहा जानकारी नहीं, एसपी ने किया लाइन हाजिर

माही की गूंज, पेटलावद/सारंगी।

पेटलावद थाने की सारंगी चौकी पर पदस्थ एएसआई नीरज सिरोही पर लोकायुक्त ने रिश्वत के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। अक्सर लोगो को रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों पकड़ते देखा हो लेकिन एक दिलचस्प मामला सामने आया है। सारंगी चौकी पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक नीरज सिरोही ने एक मामले मे दस हजार की रिश्वत की मांग की जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर पीड़ित पक्ष ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी अनुसार ग्राम कोटड़ा निवासी धारजी गामड़ के परिवार की महिला प्रेम प्रसंग के चलते भाग गई थी, जिसके बाद पुलिस चौकी में मामला सारंगी चौकी पहुँचा था लेकिन आदिवासीयो में चलने वाली भाँझगड़ी प्रथा से मामला दोनों पक्षो के बीच ग्राम पंचायत में लेनदेन के बाद राजीनामा हो गया था। बताया जा रहा है मामले की जांच बीट प्रभारी उपनिरीक्षक नीरज सिरोही द्वारा की जा रही थी जो मामला राजीनामे के बाद उप निरीक्षक अपने हिस्से के लिए रिपोर्टकर्ता से लगातार पैसे की मांग कर परेशान कर रहा था, जिससे परेशान आवेदक ने अपनी शिकायत लोकायुक्त इंदौर को दर्ज कराई। लोकायुक्त इंदौर की टीम द्वारा उप निरीक्षक नीरज सिरोही पर प्रकरण दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है लोकायुक्त पुलिस ने उप निरीक्षक की गिरफ्तारी करने हेतु सारंगी दबिश दी गई, लेकिन नीरज सिरोही नही मिले। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उप निरीक्षक को लाइन हाजिर करने की जानकारी मिल रही, तो वहीं सारंगी चौकी प्रभारी अशोक बघेल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि, उनको लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होने और उप निरीक्षक के लाइन हाजिर होने की जानकारी नही है। रिकार्डिंग के आधार पर लोकायुक्त में मामला दर्ज होने का शायद जिले का पहला मामला सामने आया है, जिससे खुलेआम रिश्वत मांगने वाले सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगने में डरेंगे।

यह घर बिकाऊ है...!

ग्राम के हिंदुओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मुस्लिम वर्ग पर लगाया धमकाने का आरोप, ज्ञापन के बाद प्रशासन पहुंचा गांव

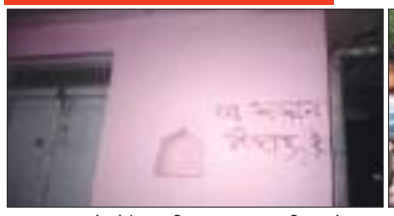

इस तरह से घरों के बहार लिखा गया यह मकान बिकाऊ है।

ज्ञापन के बाद मीडिया से हुए ग्रामिण रूबरू।

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के सुराणा ग्राम से एक अजीब मामला सामने आया, जब बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुँचे। जब ज्ञापन का विषय सामने आया तो प्रशासन के होश हवा हो गए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि, ग्राम में मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक होने से उनके द्वारा हिंदुओं को आए दिन डराया-धमकाया जाता है। पुलिस को सूचना देते हैं तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई के नाम पर बेवजह परेशान किया जाता है। पिछले दिनों हुए विवाद को लेकर एसपी से मिले तो सुनवाई के बजाए हमें ही घर तोड़ने व रासुका लगाने की धमकी दे दी। अब हमें गांव से पलायन करना है और तीन दिन में गांव खाली कर देंगे। प्रशासन हमें अन्य स्थान पर जमीन के पट्टे दे दे, जिससे हम सुरक्षित व शांतिपूर्वक रह सकें। उक्त पीड़ा ग्राम सुराना के हिंदू समुदाय के लोगों ने बयां की।

जिला मुख्यालय से करीब 13 किमी दूर बिलपांक थाना अंतर्गत स्थित इस ग्राम में इन दिनों तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 हजार 200 की आबादी वाले ग्राम की गलियों-मोहल्लों में ओटलों, चौराहों पर बैठे लोग आपस में बाते करते नजर आते हैं। लेकिन उनके बीच दूरी, अविश्वास के साथ असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुँचे जहाँ एसडीएम अभिषेक गेहलोत को ज्ञापन सोपा। बताया जा रहा है, सुराणा ग्राम में 60 प्रतिशत आबादी मुस्लिम वर्ग की ओर 40 प्रतिशत हिन्दू वर्ग की है। यहां किसी भी प्रकार का छोटा-मोटा विवाद साम्प्रदायिक विवाद का रूप ले लेता है। विगत दो तीन वर्षों से स्थिति बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि, हिन्दू वर्ग के युवाओं पर झूठे प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। मंगलवार को ग्राम में शांति स्थापित करने के लिए पहुँचे पुलिस दल ने भी दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाए रासुका, जिलाबदर और मकान तोड़ने जैसी धमकी देकर लौट गया।

डरे हुए हिन्दू परिवार, घर के बहार लिखा मकान बिकाऊ है...!

विगत एक वर्ष से ग्राम मे विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी हैं कई लोगो पर प्रकरण भी दर्ज हो चुके हैं। सुराना ग्राम का माहौल इतना बिगड़ गया कि, यहां रहने वाला हिन्दू वर्ग ग्राम छोड़ने को तैयार हो गया है। ग्राम के हिन्दू परिवारों के अधिकांश घरों के आगे ''यह मकान बिकाऊ है'' लिख दिया गया है।

मामला सामने आने के बाद एसपी गौरव तिवारी, रतलाम ग्रामीण के विधायक दिलीप मकवाना सहित प्रशासनिक अमला ग्राम के दौरे की बात कर स्थिति सामान्य करने की बात कर रहा है।

सुराना पहुँचे कलेक्टर और एसपी, प्रताड़ित परिवारों का छलका दर्द

वही ज्ञापन के बाद सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार सुबह कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर दिखा और सभी ने एक स्वर में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से परेशानी बढ़ने की बात कही। कलेक्टर ने सभी से चर्चा के बाद कहा कि, गुंडा कोई भी हो, कितना भी मजबूत दिखता हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गांव के पूर्व पटेल ओमप्रकाश जाट अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़े।

मुकेश जाट ने कहा कि, गांव में मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा-जुआ सहित अन्य अवैध काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जांच कराकर रासुका लगाने व जिलाबदर कराने की धमकी दे रही हैं। जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमको भी सुरक्षा के लिए गांव से पलायन करने का निर्णय लेना पड़ा। पिछले 2 वर्ष में जब-जब भी पुलिस को अवगत कराया, तो कार्रवाई के नाम पर हिंदू वर्ग को ही निशाना बनाया गया। चौपाल पर हिंदू वर्ग के लोगों ने अलग-अलग मामलों में अपनी पीड़ा से अवगत कराया।

ग्राम में पहुचा प्रशासन लगी चौपाल।

एसपी गौरव तिवारी ने भी सफाई देते हुए कहा कि, साल भर में जितने भी मामले हुए हैं उसमें पुलिस ने तात्कालिक तौर पर एफआइआर की है, जांच में दोषियों पर ही कार्रवाई की गई है, पुलिस विभाग ग्राम सुराना में अस्थाई पुलिस चौकी खोलेगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

पेटलावद क्षेत्र के जयस कार्यकर्ता ने लगाई रिट हुई स्वीकृत

माही की गूंज, पेटलावद।

मध्यप्रदेश में निरस्त किए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावो के बाद फिर से चुनावो की तारीख पर असमंजस की स्थिति बन गई है। हर किसी को आशंका हो चली है कि, पंचायत चुनाव लम्बे समय के लिए टल चुके हैं। इसी परपेक्ष में पेटलावद क्षेत्र के जय आदिवासी संगठन के युवा ईश्वर गरवाल और कांतिलाल गरवाल ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चुनाव जल्द करवाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विरुद्ध याचिका दायर की है।

कांतिलाल गरवाल ने बताया कि, पिछली चुनाव प्रक्रिया और न्यायलय में दिए गए समय-समय के निर्णयों को आधार बनाकर जल्द चुनाव करवाने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लगाई गई हैं, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। वही ईश्वर गरवाल ने बताया कि, मध्यप्रदेश सरकार के आरक्षण के मामले की कि गई लापरवाही के कारण लोगो को, शासन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंतिम समय मे चुनाव निरस्त करना पड़े। अब मध्यप्रदेश में जल्द से चुनाव हो इस लिए उच्च न्यायलय की शरण ली है, यहां अजाजा वर्ग सहित पिछड़ा वर्ग और अजा वर्ग द्वारा चुनाव को लेकर याचिका लगाई जा चुकी हैं।

सीईओ अमित व्यास की चालाकी से कम हुई सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें

शिकायत कर वसुली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ होने के बाद बन्द हुई थोकबंद शिकायतें

माही की गूंज, पेटलावद।

प्रसाशानिक अधिकारीयो पर खुद के कार्य के वर्क लोड के अतिरिक्त दबाव सीएम हेल्पलाइन पर रोज की जा रही सैकड़ो शिकायतो को निपटाने के दबाव रहता है। ऊपर से शिकायतो के जल्द निराकरण करने के आदेशों के बाद जिला कलेक्टर स्थानीय अमले को जल्द से जल्द अधिक शिकायतो का निराकरण करने के लिए दबाव बनाता हैं, शिकायते नही निपटने की स्थिति में अधिकारी पर गाज गिरती है। विगत दिनों पेटलावद सीईओ की चालाकी से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर पैसा कमाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। सीईओ जनपद पुलिस विभाग के अधिकारी रह चुके थे, इसलिए कानून और उसकी धाराओं का ज्ञान होने से वसुली करने वालो के विरुद्ध थाना पेटलावद में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसके बाद तीन लोग खरगोन जिले से पकड़े गए और इन्होंने कबूल किया कि, वो किस तरह से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत कर संबंधित सचिव से पैसा वसूल कर शिकायत बन्द करवाते थे।

प्रकरण बन्द होने के बाद हुई कई शिकायतें बन्द, शिकायतकर्ताओ ने मांगी माफी

मामला सज्ञान में आने के बाद कई ऐसे लोग जिन्होंने जिले के दूसरे विकास खण्ड में झूठा पता देकर रह रहे अलग अलग पंचायतो की शिकायत कर रखी थी, उन्होंने आगे रह कर शिकायते बन्द करवा दी और इसकी जानकारी सीईओ को भी दी। इतना ही नही शिकायतकर्ता ने आगे से झूठी शिकायत नही करने का आश्वासन दिया। झूठे शिकायतकर्ता इतने डर गए कि, पेटलावद थाने में दर्ज हुए प्रकरण में नाम नही लिखवाने की गुहार लगाने लग गए। बताया जा रहा है पेटलावद में फर्जी शिकायत मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद सीएम हेल्पलाइन की सैकड़ो शिकायते बन्द हो गई, तो सैकड़ो नई झूठी शिकायतो पर रोक लग गई, नए सीईओ अमित व्यास की चालाकी और समझदारी से प्रशासन पर से शिकायतो के निपटारे का बड़ा बोझ काफी हद तक कम हो गया है।

पूर्व सीईओ को मिला था प्रशस्ति पत्र

पूर्व सीईओ एनएस चौहान को जिला मुख्यालय पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतो के निराकरण करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया था। फर्जी शिकायत कर पैसा वसूलने के बाद जो मामला सामने आया उससे यही लगता है कि, इन थोक बन्द फर्जी शिकायतो को निपटाने के लिए पूर्व सीईओ द्वारा सम्बंधित पंचायतो के सचिवों पर निराकरण का दबाव बनाया जाता था और सचिव फर्जी शिकायतकर्ता द्वारा मांगी जा रही मामूली दो से तीन हजार रुपये की राशि देकर शिकायत बन्द करवा देते थे। पूरे मामले में पूर्व सीईओ की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए की आखिर एक ही नम्बर से हो रही लगातार शिकायतो को अनदेखा क्यो किया गया।

सही शिकायतो पर होंगी कार्रवाई

जनपद सीईओ अमित व्यास ने कहा है कि, इस प्रकार के प्रकरण से डरने वाली बात नही है, मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन आपकी शिकायत के समाधान के लिए बनी है और यदि आपकी शिकायत सही है तो उसकी जांच भी होगी और शिकायत सही पाए जाने पर सबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी होगी। शिकायतो की भरमार में अक्सर सही शिकायत दब जाती थी, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद हेल्पलाइन पर चल रही सही शिकायतो के निराकरण की उम्मीद लोगो मे जग गई हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422